सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 339, नई दिल्ली । शनिवार, 17 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा।

03 अलीपुर अग्निकांड मामले में सीएम ने किया मुआवजे का एलान

06 अब सुक्खू सरकार बनाएगी खेल नीति

08 बिजेड़ी-बीजेपी समझौते में ईडी ने रेड की : कांग्रेस

दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों की वाहन मालिकों से मिलीभगत के कारण जनता परेशान

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली मे मजनू टीला के पास सड़क जाम एक दैनिक समस्या है. और ऐसा इस वजह से हुआ है।

दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बना रहता है ठहराव क्योंकि दिल्ली से मनाली जाने वाली प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसे इस स्थान पर अपने बल और दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के साथ मिलीभगत कर खुले आम सवारी भरते, उठाते और उतारते हैं वह भी बेखौफ।

यह सभी गतिविधि मजनू टीला में जिस जगह होती है वह रिंग रोड पर है और इस गतिविधि के कारण समस्त जाम लगा रहता है पर कोई भी विभाग या उसके अधिकारी और कर्मचारी इन्हे कुछ नहीं बोलते जाम लगता है तो लगता रहे, जनता ही तो सिर्फ परेशान है तो क्या।

इसके प्रति जनता की और से आई है एक अच्छी राय **जिससे दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इन वाहनों के मालिको से दोस्ती भी चलती रहेगी और जनता को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा,** जाने क्या है वह रायः- दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग दिल्ली से मनाली जाने वाली बसों को मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास इन्हें जगह प्रदान कर दे जो राजमार्ग से अलग है और इन बसों में आने जाने वाली सवारियों को इन बसों तक पहुंचने और इनसे दिल्ली आई हुई सवारियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी।

ना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वाहन मालिकों से निकटता खराब होगी ना राजमार्ग पर जाम से जनता परेशान और इन बसों से आने जाने वाली सवारियों को मेट्रो सेवा उपलब्ध।

इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन/ सब्सिडी कब तक, जाने ?

सरकार ने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम-2 सब्सिडी मार्च के अंत तक या फंड उपलब्ध होने तक दी जाएगी

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड उपलब्ध होने तक दी जाएगी। सरकार ने गत शुक्रवार नौ फरवरी को इसकी जानकारी दी थी। भारी उद्योग मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में बताया गया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों को आकर्षित करने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए 'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण' योजना का दूसरा चरण सीमित फंड और अवधि का था। ऐसे में बताया जाता है कि यह योजना सीमित कोष और अवधि की है यानी मांग प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या पैसे उपलब्ध होने तक बेची गई इलेक्ट्रिक-2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक-3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक-4 व्हीलर्स के लिए होगी।

संशोधित परिव्यय के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन 7,048 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं। इसके अलावा पूंजीगत निवेश के लिए अनुदान के रूप में 4,048 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दूसरी ओर 400 करोड़ रुपये 'अदर' कैटिगरी के लिए रखे गए हैं। इस साल अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं कीं और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्टर को बेहतर बनाने पर जोर दिया हैं।

नीलामी से परिवहन निगम को हुई रिकॉर्ड इनकम, 2023-24 में अब तक 31 करोड़ से ज्यादा की कमाई

यात्रियों को परिवहन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ योगी सरकार परिवहन निगम की आय में वृद्धि को लेकर भी लगातार प्रयास कर रही है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही जनवरी तक निगम ने सिर्फ नीलामी और स्क्रैप से कमाए 31 करोड़ 37 लाख रुपए.बसों और स्क्रैप की नीलामी से निगम ने विगत 4 वर्षों में की सर्वाधिक आय, मार्च अंत तक 40 करोड़ तक पहुंच सकता है आंकड़ा.

बस यात्रियों की सुविधा के साथ ही निगम की आय में वृद्धि के लिए योगी सरकार के प्रयासों का असर

यात्रियों को परिवहन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ योगी सरकार परिवहन निगम की आय में वृद्धि को लेकर भी लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न तरह के उपाय किए गए हैं, जिनमे पुरानी खटारा बसों और स्क्रैप की नीलामी भी की जा रही है। इसके चलते परिवहन निगम को वर्ष 2023-24 में नीलामी के माध्यम से माह अप्रैल से जनवरी 2024 तक कुल 31 करोड़ 37 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हुई है, जो विगत 4 वर्षों में नीलामी से हुई आय में सर्वाधिक है। वर्ष 2022-23 में निगम को नीलामी से लगभग 10 करोड रुपए, वर्ष 2021-22 में 21 करोड़ 23 लाख रुपए एवं वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ 57 लाख रुपए की आय अर्जित हुई थी। योगी सरकार को उम्मीद है कि मार्च 2024 तक पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम को नीलामी से होने वाली आय का आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच जाएगा।

नीलामी की प्रक्रिया में आएगी तेजी

पुरानी और खटारा बसों की जगह परिवहन विभाग नई बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। ऐसे में पुरानी खटारा बसों और उससे निकलने वाले स्क्रैप की विभाग द्वारा हर वर्ष नीलामी की जाती है। परिवहन निगम के प्रबंधक (प्राविधिक) अजीत सिंह के अनुसार, सितंबर 2023 से अभी तक कुल 2050 पुरानी बसों को फ्लीट से अलग किया जा चुका है। इसमें से 1500 बसों की नीलामी हो चुकी है। बाकी बसों की नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही है। इन बसों से जो स्क्रैप सामान निकलता है उसको भी नीलाम किया जाता है। विगत 4 वर्षों में नीलामी से इस बार सबसे ज्यादा आय हुई है। नीलामी के कार्य को अत्यंत तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। पूरी संभावना है की वित्तीय वर्ष के अंत तक निगम को नीलामी के जरिए 40 करोड़ की आय हो सकेगी।

बैटरी कारोबार को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है है टाटा ग्रुप जाने

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप अपने बैटरी और ईवी बिजनेस में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रुप इस बिजनेस को अलग करने पर विचार कर रही है। बैटरी व्यवसाय को एक अलग कंपनी के रूप में स्थापित करके इसे शेयर बाजार में भी सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप एग्रेटास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को एक स्वतंत्र इकाई में बदलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समूह ऐसा करती है तो उसे बैटरी कारोबार के लिए धन जुटाने और इस कारोबार को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में मदद मिलेगी। एग्रेटास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भारत और यूके में कारखानों में ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए बैटरी डिजाइन और निर्माण करती है। इसके प्रमुख ग्राहकों में टाटा मोटर्स लिमिटेड और इसकी इकाई जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी शामिल हैं। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स यानी एसयूवी और ईवी में अपनी मजबूत पकड़ के चलते टाटा मोटर्स की पिछले महीने बिक्री के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एग्रेटास अपने कारखानों को विकसित करने के लिए हरित ऋण के माध्यम से $500 मिलियन जुटाने की तैयारी मे हैं। इसके लिए बैंकों के एक समूह से भी बातचीत की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ईवी बिजनेस को पूरी तरह से अलग करने से कंपनी इस पर ज्यादा फोकस कर सकेगी। मौजूदा समय में भारतीय ईवी बाजार में टाटा का दबदबा है।

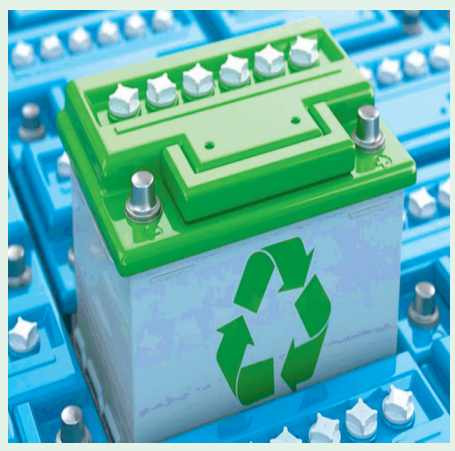

कवच' ब्रेकिंग सिस्टम के साथ किया ट्रायल, 160 की रफ्तार पर दौड़ी वंदे भारत

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा (आरएनआई) रेलवे विभाग द्वारा आठ कोच के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब 9:45 पर पलवल स्टेशन से आगे बढ़ी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ती हुई 11:28 पर मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नम्बर पांच पर पहुंची। ट्रेन को लोको पायलट डीके शर्मा चला रहे थे। बता दें उत्तर मध्य रेलवे में कवच सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है। अगर ट्रायल सफल होता है तो अन्य सवारी ट्रेनों में भी इस सिस्टम को इंजन के साथ सेट किया जाएगा। इससे ट्रेनों का संचालन बेहतर हो जाएगा। ट्रेन पर गार्ड के रूप में मलखान गुर्जर मौजूद रहे। इसके अलावा निर्देशक आरडीएसओ मधुप श्रीवास्तव , डिप्टी सीएस टीआई कुश गुप्ता, एएस टीई पीएस चंदेल समेत करीब एक दर्जन रेलवे अधिकारी और कर्मचारी ट्रायल के दौरान ट्रेन में मौजूद रहे।कवच सिस्टम लगने के बाद ट्रेन को आने वाले स्टेशन का सिग्नल एक किलोमीटर पहले ही पता लग जायेगा। अगर सिग्नल ग्रीन होगा तो ट्रेन उसी रफ्तार से आगे बढ़ जाएग । ट्रेन की रफ्तार कम नहीं करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन के लिए रुकने का सिग्नल होगा तो ड्राइवर के ब्रेक लगाए बिना ही ट्रेन ऑटोमेटिक मोड़ पर आकर सिग्नल पर खुद रुक जाएगी। इससे हादसे के ख़तरा पूरी तरह टल जाएगा।

दिल्ली में 'भारत बंद' का कितना असर

बाजार से लेकर ट्रैफिक का हाल जान लीजिए

किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद ग्रामीण का आह्वान किया गया है। बंद शाम 4 बजे तक रहेगा। हालांकि, दिल्ली के बाजार में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहां ट्रैफिक पर भी बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली : किसानों ने आज 'भारत बंद' का आह्वान किया है। इसका असर दिल्ली के बाजारों और सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। यहां रोजाना की तरह सुबह आवाजाही दिखाई दी। राजधानी के होलसेल और रिटेल बाजार भी पूरी तरह खुले हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दावा किया है कि दिल्ली में 'भारत बंद' नहीं है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी है। देर रात भी केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के मध्य चर्चा हुई। अब रविवार को भी वार्ता रखी गई है।

भारत बंद के औचित्य पर सवाल

कहा जा रहा है कि बातचीत को लेकर दोनों ओर से समाधान निकलने की बात कही जा रही है। ऐसी सूरत में 'भारत बंद' का औचित्य नहीं है। यदि किसान अन्नदाता हैं, तो व्यापारी करदाता है, जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। राष्ट्रीय खजाने में व्यापारियों का योगदान कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए। प्रवीण ने कहा कि अभी दिल्ली-यूपी और दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने सख्त पहरा लगा रखा है। बैरिकेडिंग की वजह से सुबह और शाम को बॉर्डर पर जाम की स्थिति हो रही है। आम लोगों को आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्ड पर ज्यादा समस्या है। यहां भारी पुलिस फोर्स और किसानों को थामने का प्रबंध किया है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई असर नहीं

ऑटो रिक्शा, टैक्सी, माल वाहक वाहन रोजाना की तरह से सड़कों पर चल रहें हैं। 'भारत बंद' का दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई असर नहीं देखा गया। इसका सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया। हम ऑटो रिक्शा, टैक्सी और माल वाहकों के चालकों और मालिकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 'भारत बंद' में हिस्सा नहीं लिया है। इन दिनों शादी-ब्याह का सीजन है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। कोई भी व्यापारी सीजन में बिजनेस चौपट नहीं करना चाहता है। दिल्ली के बाहर से आने वालों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी को दो पैसा कमाने का अवसर मिल रहा है। आम जनों को गुमराह करने वालों को पहचाने की जरूरत है। किसानों की मांगों पर सरकार गंभीर है। बातचीत हो रही है। जल्द समाधान निकलेगा।

चांदनी चौक के बाजार पूरी तरह खुले

दिल्ली के बाजार पूरी तरह से खुले है। चांदनी चौक में सभी कटरे, कूचे, गली में रोजाना की तरह कपड़े की दुकान, शोरूम और गोदाम में काम चल रहा है। साथ ही यहां के खाने-पीने के ठियों पर भी आम दिनों की भीड़ है। मगर, ये कह सकते हैं कि व्यापारियों के माल 2-3 दिनों से ट्रांसपोर्ट से नहीं आए हैं। बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली आने वाले दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहकों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। इसका असर कपड़ा मंडी के कामकाज पर पड़ा है। अभी जो भारतीय रेल और दिल्ली से आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से आवक ठप है। सोनीपत से आने वालों को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए काफी घूमना पड़ रहा है। इसमें लंबा समय रहा है। व्यापारी चाहते हैं कि मसला जल्दी सुलझे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

सर्वाइकल कैंसर का खतरा युवा महिलाओं को ज्यादा, अपोलो की डॉक्टर सारिका गुप्ता ने बताए बचाव के तरीके

कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि की वजह से हो जाता है. कैंसर कई तरह के होते हैं. इनमें से एक सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) होता है, जो महिलाओं में होने वाला कॉमन कैंसर है. दुनियाभर में हर साल बड़ी तादाद में महिलाएं महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं. चिंताजनक बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम उम्र की महिलाओं को ज्यादा होता है. आज कैंसर स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है.

नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सारिका गुप्ता के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की बच्चेदानी के मुख में होने वाला कैंसर है. इसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है. आमतौर पर 35 साल से लेकर 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. यह कैंसर दो तरह का होता है- पहला लो ग्रेड और दूसरा हाई ग्रेड. लो ग्रेड कैंसर धीरे-धीरे फैलता है, जबकि हाई ग्रेड कैंसर तेजी से फैलता है और इसमें मौत का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में सही वक्त पर इलाज कराना बेहद जरूरी है.

ऐसी महिलाओं को खतरा ज्यादा

डॉक्टर सारिका गुप्ता कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो और एचआईवी या अन्य कोई गंभीर बीमारी हो. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जेनिटल हाइजीन की कमी और जल्दी बच्चे होने वाली महिलाओं को इसका जोखिम ज्यादा होता है. इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को इससे बचने के लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग करानी चाहिए. सर्वाइकल कैंसर का पता प्री-कैंसरस स्टेज में भी लगाया जा सकता है और सही इलाज के जरिए कैंसर से बचा भी जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

– पार्टनर के साथ संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग
– पीरियड्स के बीच अनियमित माहवारी होना
– बदबूदार पानी आना या ब्लड स्ट्रीम डिस्चार्ज
– मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना

सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट और बचाव

डॉक्टर के अनुसार सर्वाइकल कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में हो, तो सर्जरी के जरिए इसका इलाज किया जाता है. एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी की जरूरत होती है. हर मरीज की कंडीशन को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है. जितना जल्दी इसका पता लग जाए, मौत का खतरा उतना कम हो सकता है. बचाव की बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV का टीका लगवाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. स्मोकिंग से दूरी बनाएं और संबंध बनाते वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें. समय-समय पर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच करवाएं.

5 सेफ्टी टूल्स महिलाएं हैंड बैग में जरूर रखें साथ

मुसीबत में आएंगे बहुत काम कैरी करने में भी नहीं होगी दिक्कत

अकेले ट्रैवल करते समय ज्यादातर महिलाएं अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित रहती हैं. खासकर शाम या रात के वक्त महिलाओं का अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं होता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो हैंड बैग में अपने साथ कुछ सेफ्टी टूल्स (Safety tools) रख सकती हैं. जो कि ना सिर्फ मुसीबत में आपके काम आएंगे बल्कि इन्हें कैरी करने में भी आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी. घर से निकलते समय ज्यादातर महिलाएं हैंड बैग में मेकअप प्रोडक्ट्स जैसी जरूरत की सारी चीजें रखती हैं. मगर ऐसे में कई महिलाएं अक्सर अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देती हैं. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कुछ वुमन सेफ्टी टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अकेले भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चत कर सकती हैं.

पेपर स्प्रे रखें: महिलाओं के लिए हैंड बैग में पेपर स्प्रे रखना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. पेपर स्प्रे की छोटी सी बोतल आपको बड़ी परेशानी से दूर रखने में सहायक हो सकती है. वहीं मार्किट में भी पेपर स्प्रे की अलग-अलग साइज की बोतलें आसानी से मिल जाती है.

कैंची रखें: ऑफिस पर्पस या रोजमर्रा के अन्य कामों में कैंची का इस्तेमाल काफी कॉमन होता है. ऐसे में आप अपने साथ हैंड बैग में कैंची भी रख सकती हैं. इससे ना सिर्फ आप कई कामों को आसान बना सकती हैं बल्कि अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती हैं.

सेफ्टी पिन यूज करें: सेफ्टी पिन का इस्तेमाल महिलाओं के डेली रूटीन में आम होता है. आमतौर पर ड्रेस को टक करने के लिए महिलाएं सेफ्टी पिन की मदद लेती हैं. मगर सेफ्टी पिन आपके लिए बेस्ट सेफ्टी टूल भी साबित हो सकती है. इसे हमलावर पर चुभाकर आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं.

नेलकटर या स्विस नाइफ कैरी करें: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं अपने बैग में नेलकटर या चाकू कैरी कर सकती हैं. खासकर स्विस नाइफ रखना आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. जिसकी मदद से आप हमलावार पर तुरंत पलटवार कर सकती हैं.

चाबी की मदद लें: अकेले सफर करने के दौरान चाबी का इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं. हमलावर के अटैक करते ही आप चाबी के नुकीले हिस्से की मदद से तुरंत रिएक्ट कर सकती हैं. इसलिए घर से निकलते समय किसी बड़ी नुकीली चाबी को हैंड बैग में जरूर रख लें.

व्हट्सअप चैट करने में महिलाएं पुरुषों से आगे, सर्वे में खुलासा, मेंटल हेल्थ से जुड़ा है मामला

व्हाट्सएप पर चैट करने में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं. हाल ही में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन (Mental Health Helpline) की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि टेलिफोन पर कंसल्टेशन या काउंसलिंग लेने के बजाय महिलाएं व्हाट्सएप चैट (WhatsApp Chat) के माध्यम से गोपनीय तरीके से मदद लेना पसंद करती हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स फेसबुक (Facebook), ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हाट्सएप (WhatsApp) या अन्य किसी भी एप्लिकेशन का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. चाहे किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो, मनोरंजन करना हो, जानकारी लेनी-देनी हो या सगे-संबंधियों से बातचीत करनी हो तो लोग इन एप्स (App) का इस्तेमाल करते हैं. कभी-कभी चैट में मैसेज टाइप करते-करते उलझन सी भी महसूस की होगी लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है. व्हाट्सएप पर चैट करना (WhatsApp Chatting) महिलाओं को न केवल फोन पर बात करने के मुकाबले ज्यादा आसान लगता है बल्कि कॉनफिडेंशियल भी लगता है. वे व्हाट्सएप चैट करने में पुरुषों से काफी आगे हैं. खास बात है कि ये चैट भी इस हेल्पलाइन 9999666555 नंबर पर की गई है जो एक मेंटल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का है.

मानसिक स्वास्थ्य संगठन वंद्रेवाला फाउंडेशन की फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन के 3 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर मेंटल इश्यूज को लेकर सलाह और परामर्श लेने वालों में युवा आबादी ने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का उपयोग किया है. जबकि मध्यम आयु वर्ग और उससे ऊपर के लोगों ने टेलीफोनिक बातचीत को अधिक पसंद किया.

आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश युवा अपने मानसिक स्वास्थ्य की मदद के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं और इसे बेहतर मानते हैं. 18 वर्ष से कम आयु के 65 फीसदी, 18-35 आयु वर्ग के 50 फीसदी, 35-60 आयु वर्ग के 28.3% और 60 वर्ष से अधिक आयु के 8 फीसदी लोगों ने मेंटल हेल्थ के लिए व्हाट्सएप यूज किया है.

53 फीसदी महिलाएं जबकि पुरुष 42 फीसदी..

फाउंडेशन के डेटा के अनुसार लगभग 53 फीसदी महिलाएं व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके हेल्पलाइन से संपर्क करना पसंद करती हैं, जबकि 42 फीसदी पुरुष व्हाट्सएप चैट का उपयोग करना पसंद करते हैं. वहीं बाकी मामलों में लोग टेलिफोन के द्वारा काउंसलिंग लेते हैं.

खास बात है कि व्हाट्सएप ने उस वर्ग को सबसे ज्यादा राहत दी है जो शायद कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता ऑफलाइन क्लीनिकों पर जाकर नहीं ले सकता था. खासतौर पर ऐसी महिलाएं, लड़कियां और युवक जो अपने परिवार या साथियों को बिना बताए अपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं वे व्हाट्सएप का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. वे इसे गोपनीय मानते हैं और समय की उपलब्धता के अनुसार साइलेंट तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर पाते हैं.

सुसाइड के विचारों से जूझ रहे लोग

फाउंडेशन की प्रमुख और परोपकारी, प्रिया हीरानंदानी वंद्रेवाला कहती हैं, 'हमसे संपर्क करने वाले एक तिहाई लोगों ने हमें बताया कि वे मानसिक बीमारी, चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं. 2022 में भारत में हत्याओं और कोरोना वायरस से ज्यादा जानें आत्महत्या ने लीं. भले ही आज देश का हर मेडिकल छात्र मनोचिकित्सक बन गया हो, हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य संकट को हल करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं. इसके साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए मदद लेने वाले लोगों के मन में झिझक और डर को दूर करने की भी जरूरत है.

30 की उम्र में हर महिला जरूर कराएं ये 10 टेस्ट, कई घातक बीमारियों से रहेंगी महफूज, डॉक्टर ने बताई असली वजह

अगर आप 30 साल की हो गई हैं तो समय आ गया है कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को गंभीरता से लें. अगर आप 30 साल की हो गई हैं तो समय आ गया है कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को गंभीरता से लें.

30 की उम्र के बाद महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. उनके हॉर्मोन्स में असंतुलन होने लगता है. ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सेहत को बनाए रखना और इन बदलावों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है. यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो डॉ. सारिका गुप्ता के बताए इन महत्वपूर्ण टेस्ट को ज़रूर करा लें.

महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं. ये बदलाव उनके लुक, हड्डियों, हॉर्मोन्स और समग्र स्वास्थ्य में हो सकते हैं. 30 की उम्र के बाद महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. उनके हॉर्मोन्स में असंतुलन होने लगता है. मांसपेशियों की क्षमता कम होने लगती है और यहां तक की प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सेहत को बनाए रखना और इन बदलावों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है. यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो आप इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल (नई दिल्ली) की ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक गायनोकोलॉजी की सीनियर कंसलटेंट डॉ. सारिका गुप्ता के बताए इन महत्वपूर्ण टेस्ट को ज़रूर करा लें, ताकि आप लंबी उम्र तक स्वस्थ और फिट रह सकें.

थायराइड फंक्शन टेस्टः थायरॉक्सिन (टी4) और ट्राईआयोडोथॉयरोनिन (टी3), ये थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले दो प्रमुख हॉर्मोन हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज़्म पर नियंत्रण बनाए रखते हैं. अगर ये हॉर्मोन सामान्य से अधिक या कम मात्रा में बनने लगें तो इसे क्रमशः हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. महिलाओं में थायराइड से जुड़ी समस्याओं की संभावना पुरुषों की तुलना में अधिक होती है. आप थायराइड फंक्शन टेस्ट के द्वारा पता लगा सकती हैं कि आपके शरीर में थायराइड हॉर्मोंस का स्तर सामान्य है या नहीं.

पैप स्मियर टेस्ट और पेल्विक जांचः पैप स्मियर टेस्ट में सर्विक्स की सेल्स की जांच कर यह पता लगाया जाता है कि महिला में सर्वाइकल कैंसर की संभावना तो नहीं. इस जांच के द्वारा सर्वाइकल कैंसर का निदान बहुत जल्दी हो जाता है. इससे समय पर इलाज किया जा सकता है. इसके अलावा, पेल्विक जांच में महिला के प्रजनन अंगों जैसे वल्वा, गर्भाशय, वेजाइना, ओवरीज आदि की जांच की जाती है. सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि 21 साल की उम्र के बाद उन्हें हर दो या तीन साल बाद नियमित रूप से पेल्विक जांच एवं पैप स्मियर टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए.

मैमोग्राम टेस्टः मैमोग्राम में डॉक्टर स्तनों की स्क्रीनिंग कर स्तन कैंसर का पता लगाते हैं. 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना अधिक होती है. हालांकि, समय पर निदान के द्वारा महिला की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है. कैंसर के फैलने से पहले ही अगर इलाज हो जाए तो मरीज के जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है. इसके लिए मैमोग्राम बहुत उपयोगी है, जो कैंसर के जल्द निदान में मदद करता है.

ब्लड प्रेशर और कॉलेस्ट्रॉल की जांचः अगर आप 30 साल की हो गई हैं तो समय आ गया है कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को गंभीरता से लें. 20 साल की उम्र के बाद हर व्यस्क को हर दो साल में ब्लड प्रेशर और कॉलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए. चाहे आप अपने आप को कितना ही स्वस्थ महसूस करती हों, आपको अपना कॉलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाना चाहिए. वजन अधिक है या डायबिटीज है, तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक होती है.

कैल्शियम और विटामिन डी टेस्टः ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बोन डेंसिटी ठीक बनाए रखें. ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, जो दुनिया भर में बड़ी संख्या में महिलाओं में पाई जाती है. हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने विटामिन डी और कैल्शियम के स्तर पर निगरानी रखें. नियमित जांच के द्वारा आप तय कर सकती हैं कि क्या आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं. ब्लड शुगर लेवल की जांच भी है जरूरीः उपरोक्त हेल्थ चेकअप के अलावा, महिलाओं को अपने ब्लड शुगर, त्वचा में होने वाले बदलावों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 30 की उम्र के बाद नए मस्से, तिल होना आम बात है. साथ ही हर 6 महीने में अपना फुल-बॉडी चेकअप कराना न भूलें.

द्वारका एक्सप्रेसवे जल्द ही खुलने वाला है, लेकिन फंसा हुआ है एक पेंच!

भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे जल्द ही यातायात के लिए खुल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, एक्सप्रेसवे के गुड़गांव सेगमेंट को मार्च के पहले सप्ताह तक खोले जाने की उम्मीद है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे, (द्वारका एक्सप्रेसवे) जल्द ही यातायात के लिए खुल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के मुताबिक, एक्सप्रेसवे के गुड़गांव सेगमेंट को मार्च के पहले सप्ताह तक खोले जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने तक द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं।

गडकरी ने हाल ही में कहा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली और गुड़गांव के बीच यातायात प्रवाह को आसान बनाने वाले इस एक्सप्रेसवे को आखिरी रूप दिया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट लगाने, सड़क पर लेन को मार्क करने जैसे छोटे-मोटे कार्य किए जा रहे हैं, जो कुछ हफ्तों में पूरे होने की उम्मीद है। हालांकि, दिल्ली सेगमेंट को पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य का सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि करीब 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है। गडकरी ने कहा, ₹हमने प्रधानमंत्री से UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरे किए गए पैकेजों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में हमें उनका समय मिलेगा और हम इन सड़कों का उद्घाट करेंगे।₹

द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है, 29 किलोमीटर लंबा 16 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुड़गांव से जोड़ता है। यह NH-8 या दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर शिव-मूर्ति से शुरू होता है और द्वारका सेक्टर 21, गुड़गांव बॉर्डर और बसाई के जरिए खेरकी दौला टोल प्लाजा के पास खत्म होता है। एक्सप्रेसवे का करीब 19 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में आता है। जबकि बाकी 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। द्वारका एक्सप्रेसवे में 3.6 किलोमीटर लंबा और 8 लेन चौड़ा सबसे लंबा और चौड़ा शहरी रोड टनल भी होगा।

नए एक्सप्रेसवे से उम्मीद है कि यात्रियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रूट मिलेगा। यह नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैफिक को भी करीब 50 फसदी कम करने में मदद करेगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे अद्वितीय विशेषताओं के साथ एक मेगा स्ट्रक्च है। 9,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, इसमें करीब 2.07 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रतिष्ठित एफिल टॉवर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए स्टील से 30 गुना ज्यादा है। एक्सप्रेसवे में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कंक्रीट से 6 गुना ज्यादा है।

दिल्ली में द्रोणागिरी हॉस्टल में रहने वाले आईआईटी छात्र ने की खुदकुशी

दिल्ली के आईआईटी कैंपस के द्रोणागिरी हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने अपनी जान दे दी। छात्र की पहचान हो गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक, आईआईटी कैंपस के द्रोणागिरी हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने अपनी जान दे दी। छात्र की पहचान हो गई है। छात्र का नाम वरद संजय नेरकर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 साल है। जो नासिक का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि छात्र ने बेडशीट के सहारे छत के पंखे से लटककर जान दे दी। छात्र का फोन परिवार से नहीं मिल रहा था। इसलिए एक दोस्त ने आईआईटी कैंपस के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। मृतक एमटेक फाइनल ईयर का छात्र था। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जहां से भरी उड़ान, ढाई घंटे बाद वहीं पहुंचे वापस; इंडिगो फ्लाइट की इस घटना से आप भी हो जाएंगे हैरान

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में लोगों के साथ अजीब वाकया हुआ। बृहस्पतिवार को वाराणसी जाने के लिए इंडिगो के विमान में यात्री इस उम्मीद से सवार हुए कि वे करीब एक घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। विमान अपने तय समय पर उड़ान भरा और तय समय पर ही वाराणसी पहुंचा। हालांक ढाई घंटे बाद लोगों ने जहां से उड़ान भरी थी वहीं पर खुद को पाया।

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को वाराणसी जाने के लिए इंडिगो के विमान में यात्री इस उम्मीद से सवार हुए कि वे करीब एक घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। विमान तय अवधि में वाराणसी पहुंचा, लेकिन लैंडिंग के बजाय विमान ने वापस नई दिल्ली की राह पकड़ ली।

यात्री भी घटना से आश्चर्यचकित

जब विमान नई दिल्ली पहुंचा, तब यात्रियों को आश्चर्य हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में इंडिगो प्रबंधन कुछ भी नहीं बता रहा है। हालांकि एक यात्री ने जब इस प्रकरण से इंडिगो को अवगत कराया तो इंडिगो की ओर से केवल चिंता जताई गई।

ढाई घंटे बाद वहीं वापस लौटे

उड़ान संख्या 6 ई 2235 ने आईजीआई एयरपोर्ट से निर्धारित तय समय से करीब 19 मिनट की देरी से 8.19 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरी, लेकिन विमान करीब ढाई घंटे के बाद वापस नई दिल्ली लौट आया।

एयर पोर्ट पर टला बड़ा हादसा

वहीं, 11 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। अमृतसर से इंडिगो का एक विमान रविवार सुबह दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के बाद टैक्सीवे (टैक्सीवे हवाईअड्डे पर विमानों के लिए एक रास्ता है जो रनवे को एप्रन, हैंगर, टर्मिनल और अन्य सुविधाओं से जोड़ता है) को पार कर गया था।

घटना के कारण रनवे लगभग 15 मिनट तक अवरुद्ध रहा और कुछ उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। जानकारी में यह भी बताया गया कि बाद में इंडिगो की एक टोइंग वैन विमान को रनवे के अंतिम छोर से पार्किंग बे तक ले गई।

लोकनायक में जल्द शुरू होगी बच्चों की रोबोटिक सर्जरी, आसान होगा इलाज

लोकनायक अस्पताल में जल्द ही बच्चों की रोबोटिक सर्जरी शुरू होने वाली है। इस सर्जरी की मदद से बच्चों का इलाज आसान होगा। बाल शल्य चिकित्सा विभाग की अध्यक्ष डॉ. सिम्मी के रतन ने बताया कि यह सुविधा शुरू होने के बाद मरीजों को एडवांस सेवाएं मिल पाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े लोकनायक अस्पताल में जल्द ही बच्चों की रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। मौजूदा समय में यहां सामान्य सर्जरी के अलावा एडवांस लेप्रोस्कोपिक की सेवाएं मिल रही हैं। अस्पताल को नया भवन मिल जाने के बाद विभाग में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। इससे मरीजों का इलाज आसान होगा।

साथ ही रिकवरी भी तेज होगी। विशेषज्ञों की मानें तो अस्पताल में हर साल हजारों बाल मरीज भर्ती होते हैं। अभी रोजाना औसतन सात बच्चों की माइनर और जटिल सर्जरी हो रही है। इस बारे में बाल शल्य चिकित्सा विभाग की अध्यक्ष डॉ. सिम्मी के रतन ने बताया कि यह सुविधा शुरू होने के बाद मरीजों को एडवांस सेवाएं मिल पाएगी। मौजूदा समय में यहां रोजाना सात बच्चों की सर्जरी हो रही है। अस्पताल में हर साल माइनर और जटिल चार हजार सर्जरी होती हैं।

कार्यशाला आयोजित

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बाल शल्य चिकित्सा सुविधा को एडवांस करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बच्चों की सर्जरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. पूनम नारंग, डॉ. सुजॉय नियोगी, डॉ. प्रफुल्ल कुमार, डॉ. गौरव सक्सेना, डॉ. मोहम्मद फहीम अहमद सहित अन्य ने बाल शल्य चिकित्सा पर अपनी बात रखी। साथ ही पुस्तक का विमोचन किया।

इन जटिल सर्जरी की सुविधा

- जन्म से खाने की नली न होना, जन्म से शौच का रास्ता न होना
- पेशाब में रुकावट, पेशाब की थैली छोटा या खुला होना
- गुर्दे की नली में रुकावट, छाती में गांठ
- छाती और पेट के बीच में पर्दा की दिक्कत सामने के हिस्से में पेट न बना होना
- पित की थैली न बनना
- जन्म से पीलिया होना
- शारीरिक बनावट में दिक्कत
- अंतड़ियों में रुकावट
- चोट लगना, छत से गिरकर व अन्य, बायोप्सी

इन बच्चों में दिक्कत

- गर्भावस्था के दौरान मां को इंफेक्शन हो, बच्चे में जेनेटिक समस्या रही हो
- जन्म के दौरान लिंग स्पष्ट न हो, जेनेटिक कैंसर के कारण हो
- मां अत्याधिक धूम्रपान या नशा करती हो, मां को वायरल इंफेक्शन रहा हो

बच्चे पी रहे टॉयलेट क्लीनर

छोटे बच्चे अक्सर हाथ में आने वाली वस्तु को मुंह में डाल लेते हैं। ऐसे मामलों में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोकनायक अस्पताल में ऐसे कई बच्चे सर्जरी के लिए लाए गए, जिन्होंने लापरवाही में टॉयलेट क्लीनर, एसिड या अन्य पदार्थ पी लिया हो।

भाजपा के सात विधायक निलंबित, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी बोले- वापसी तक लड़ाई जारी

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा के सात विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा के सात विधायकों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा। समिति की रिपोर्ट आने तक विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सात विधायकों को निलंबित कर दिया। अब सदन में केवल नेता प्रतिपक्ष भाजपा के विधायक के तौर पर रहेंगे।

रामवीर सिंह विधूड़ी बोले- ये लोकतंत्र की हत्या

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से भाजपा विधायकों को निलंबित किया है। विधानसभा में जब उपराज्यपाल का भाषण होता है तो उस दौरान सदन की शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं होती है।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई और कदम उठाए जा सकेगा वह भी उठाएगे। भाजपा विधायकों की सदन में वापसी नहीं होने तक वह लड़ाई लड़ते रहेंगें।

विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी: भाजपा

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अभिभाषण में बाधा डालने के कारण कल उनको सदन से मार्शल आउट कर दिया गया था। उप राज्यपाल के भाषण के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। तब विधानसभा अध्यक्ष ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीय इस कारण इस मामले में उनको सजा मिल चुकी है। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने एक मामले में दो बार सजा देने का काम किया है। जबकि किसी भी अपराध व आरोप में दो बार सजा देने का प्रावधान नहीं है। उनको एक साजिश के तहत विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी है।

इस दर्दनाक हादसे में पुलिसकर्मी करमबीर सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

अलीपुर अग्निकांड मामले में सीएम ने किया मुआवजे का एलान, फैक्टरी के खिलाफ होगी कार्रवाई; 11 की मौत

दमकलकर्मियों ने घरों की छतों पर चढ़कर आग बुझाई। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के चलते इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। आग पर काबू पा लिया गया है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अलीपुर में एक पेंट फैक्टरी में आग लगने से 11 लोगों की मौत के बाद दमकल कर्मियों का तलाशी अभियान जारी है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक, फैक्टरी में दो और लोगों के फंसे होने की संभावना है। अग्निकांड मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या की प्रयास की धारा 304 और 308 के तहत मामला दर्ज किया है।

सीएम केजरीवाल ने किया मुआवजे का एलान

घटना स्थल का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है। हम मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 20 हजार रुपये देंगे। सीएम ने साथ ही कहा कि दमकल की गाड़ियां देर से पहुंचीं। इसकी जानकारी मिली। मैं इसकी जांच के आदेश दूंगा। फैक्टरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम केजरीवाल ने किया दौरा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर का दौरा किया। इस दर्दनाक हादसे में पुलिसकर्मी करमबीर सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। करमबीर साहस दिखाकर आग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बृहस्पतिवार शाम 5:25 बजे हुआ, जिस पर दमकल की 22 गाड़ियों की मदद से करीब तीन घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। आग की चपेट में पांच दुकानें व गाड़ियां भी आ गईं। आग का कारण पता नहीं चला है। फरार फैक्टरी मालिक अखिल की तलाश की जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

अब तक 11 लोगों की मौत

अग्निशमन विभाग ने बताया कि दो पेंट और केमिकल गोदामों में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं चार घायल हैं। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया है। लोकनायक अस्पताल में दो मरीज भर्ती हुए है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार के मुताबिक, दो लोगों को सांस लेने में दिक्कत के कारण भर्ती किया गया है। दोनों की हालत स्थिर है। किसी भी जले हुए मरीज को अस्पताल में लाया नही गया। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। दोनों की हालत स्थिर है।

घायलों की पहचान

1. ज्योति पत्नी सुनील उम्र 42 वर्ष
2. दिव्या पुत्री सुनील 20 वर्ष
3. मोहित सोलंकी पुत्र जगत सोलंकी 34 वर्ष।
4. कांस्टेबल करमबीर

काफी मात्रा में जमा था केमिकल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के बाद फैक्टरी में कई धमाके हुए। रिहायशी इलाके में होने की वजह से आग से वहां दहशत फैल गई। फैक्टरी में 24 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। वहां काफी मात्रा में केमिकल था। आग नजदीकी घरों में फैलने से दीवारें तपने लगीं। पुलिस ने वहां रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। फैक्टरी का धुआं नजदीकी घरों में भी घुस गया।

आग लगते ही मच गई भगदड़, कई लोग घायल

अलीपुर के रिहायशी इलाके में फैक्टरी में आग लगने के बाद कई धमाके हुए। इससे आग तेजी से फैल गई और चीख-पुकार के बीच लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। भगदड़ के बीच कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए। जबकि मौके का फायदा उठाकर हरियाणा निवासी फैक्टरी का मालिक अखिल जैन फरार हो गया। घटना के बाद कर्मचारियों ने संपर्क करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वह गुवाहाटी में है।

वहीं, आग ने स्टेशनरी व टेलर की दुकान, सैलून, ढाबा, किराना स्टोर व सामने वाले घरों को चपेट में ले लिया। इससे सामने वाले घर में रहने वाले तीन लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि दुकानों व घरों में रखा सामान जल गया। इसके अलावा फैक्टरी के अंदर खड़े वाहन और बाहर स्कार्पियों व बाइक भी जल गई। स्थानीय लोग व दमकलकर्मी घरों की छत से आग बुझाने में जुट गए।

लोगों का कहना है कि फैक्टरी में करीब 12 लोग हताहत हो सकते हैं। वहीं, दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटना के समय 24 लोगों के फैक्टरी में होने की जानकारी मिली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्टरी में करीब तीन दर्जन से अधिक केमिकल के ड्रम व काफी मात्रा में पेंट के डब्बे रखे हुए थे। ज्वलनशील पदार्थ होने से आग तेजी से फैल गई।

जेसीबी मंगवाकर शुरू कराया तलाशी अभियान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग लगने से फैक्टरी का फर्श काफी गर्म हो गया था। इसे देखते हुए देर रात करीब 11 बजे जेसीबी मंगवाकर तलाशी अभियान शुरू किया गया।

नशा मुक्ति केंद्र के लोगों को बाहर निकाला

फैक्टरी के सामने एक नशा मुक्ति केंद्र भी है। धमाके के बाद इसमें आग लग गई थी। स्थानीय लोगों व पुलिस ने समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया।

अपनों की तलाश में जुटे लोग

घटना की जानकारी मिलने के बाद से अपनों की तलाश में कई लोग फैक्टरी पहुंच गए। सुनील ठाकुर ने बताया कि भाई अनिल ठाकुर फैक्टरी में काम करता था। भाई से मोबाइल के जरिये संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। फैक्टरी से मिले शव इतने झुलस गए हैं कि पहचान पाना मुश्किल है। एक अन्य युवक ने बताया कि छोटा भाई हुकुम भी यहां काम करता था। शाम पांच बजे के बाद से उसका फोन बंद है।

आग की हाल की घटनाएं

19 जनवरी 2024: पीतमपुरा में घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत।

27 जनवरी 2024: शाहदरा में इमारत में आग लगने से 9 माह के बच्चे समेत चार लोगों की मौत।

15 नवंबर 2023: शकरपुर में चार मंजिल इमारत में लगी आग। जान बचाने के लिए कई लोग नीचे कूदे। महिला की मौत व दमकलकर्मी समेत 19 लोग झुलसे।

मेवाड़ कॉलेज के सामने तीन मंजिला मकान में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित मेवाड़ कॉलेज के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं और घटना में अभी कोई हताहत नहीं है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित मेवाड़ कॉलेज के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं और घटना में अभी कोई हताहत नहीं है।

श्रीरामलला के दर्शन के लिए 80 बसों में भाजपा नेता अयोध्या रवाना, शुक्रवार को लौटेंगे

श्रीरामलला के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद से 80 बसों में लगभग चार हजार भाजपा नेता बृहस्पतिवार को अयोध्या रवाना हुए। इसके अलावा कुछ नेता निजी कारों से भी अयोध्या गए। श्रीरामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भाजपा ने प्रत्येक जिले से भाजपा नेताओं को अयोध्या ले जाने का कार्यक्रम तय किया। इसके तहत 15 फरवरी की तारीख तय की गई थी।

गाजियाबाद। श्रीराम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में विराजे श्रीरामलला के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद से 80 बसों में लगभग चार हजार भाजपा नेता बृहस्पतिवार को अयोध्या रवाना हुए। इसके अलावा कुछ नेता निजी कारों से भी अयोध्या गए।

श्रीरामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भाजपा ने प्रत्येक जिले से भाजपा नेताओं को अयोध्या ले जाने का कार्यक्रम तय किया। इसके तहत 15 फरवरी की तारीख गाजियाबाद के भाजपा नेताओं के लिए तय की गई थी।

चार हजार बीजेपी नेता अयोध्या रवाना

महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में प्रत्येक बूथ से दो पदाधिकारियों को अयोध्या ले जाने की व्यवस्था की गई। बृहस्पतिवार को गाजियाबाद में अलग-अलग स्थानों से कुल 80 बसों में लगभग चार हजार भाजपा नेता अयोध्या रवाना हुए हैं। श्रीरामलला के दर्शन के बाद शुक्रवार को वहां से भाजपा नेता वापस लौटेंगे।

किसानों के दिल्ली कूच से साइबर सिटी को 200 करोड़ का नुकसान, 10 दिन बाद स्थिति और होगी खराब

परिवहन विशेष न्यूज

किसानों के दिल्ली कूच से साइबर सिटी को 200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। पंजाब से कारोबार पूरी तरह ठप है। वहां से न माल आ पा रहा है और न ही जा पा रहा है। हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के भी अधिकतर इलाकों में ट्रांसपोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। कुछ इलाकों में जा पा रहे हैं तो काफी दूरी तय करके।

गुरुग्राम। किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा से चार दिनों के भीतर साइबर सिटी को लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यदि भय का माहौल 10 दिन से अधिक रहा फिर प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान साइबर सिटी को झेलना पड़ेगा।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में न माल जा पा रहा है और न ही वहां से माल आ पा रहा है। जिन इलाकों में माल जा पा रहा है वह काफी दूरी तय करके। इस वजह से माल ढुलाई का खर्च काफी अधिक पड़ रहा है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत के इलाकों में भी माल की आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है।

ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे अधिक असर

साइबर सिटी ऑटोमोबाइल एवं गारमेंट का हब है। दोनों सेक्टर से हजारों ट्रांसपोर्ट जुड़े हैं। माल्ट एक्सट्रैक्ट का भी हब साइबर सिटी है। किसानों की दिल्ली कूच से ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे अधिक असर है। पंजाब से कारोबार पूरी तरह ठप है। वहां से न माल आ पा रहा है और न ही जा पा रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के भी अधिकतर इलाकों में ट्रांसपोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। कुछ इलाकों में जा पा रहे हैं तो काफी दूरी तय करके। इससे ढुलाई का खर्च काफी अधिक पड़ रहा है।

सप्लाई चेन टूटने से होगा भारी नुकसान

उद्यमियों का कहना है कि अभी भी औद्योगिक इकाइयों के पास रॉ-मेटेरियल है। सभी के पास 10 से 15 दिन का स्टॉक होता है। यदि माहौल इसी तरह का रहा अगले कुछ दिनों तक रहा वैसे में सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाएगा। सप्लाई चेन टूटने का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बार सप्लाई चेन टूटने का असर लगातार कई दिनों तक रहता है।

लुधियाना से माल निकलना पूरी तरह ठप

पंजाब का लुधियाना ऑटो कंपोनेंट का ही नहीं बल्कि गारमेंट हब भी है। साइबर सिटी से लेकर पूरे देश में लुधियाना से टीशर्ट सहित कई प्रकार के कपड़े जाते हैं। लुधियाना से माल निकलना पूरी तरह ठप है। इसी तरह मंडी गोविंदगढ़ से कच्चा लोहा पूरे देश में पहुंचता है। वहां से भी माल निकलना पूरी तरह ठप है।

एक बार फिर उद्योग जगत संकट में है। पहले किसानों के प्रदर्शन के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कोरोना संकट से भी भारी नुकसान हुआ था। अब नया संकट सामने है। इसे झेलना बहुत मुश्किल होगा। जितनी जल्द हो माहौल को बेहतर किया जाए। माल का पेमेंट जब रूक जाएगा फिर कारोबार ही ठप हो जाएगा। - ***दिनेश अग्रवाल, उद्योगपति, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन***

पंजाब में ट्रांसपोर्ट का जाना सौ फीसद बंद है। आसपास के कई राज्यों में भी बहुत कम ट्रांसपोर्ट जा पा रहे हैं। यही नहीं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी ट्रांसपोर्ट के जाने में परेशानी हो रही है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड होकर ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत के अधिकतर इलाकों में जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 40 प्रतिशत कारोबार ठप है। - ***विनोद शर्मा, उपाध्यक्ष, आल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन***

अधिकतर उद्योग के पास 10 से 15 दिन का ही रॉ मेटेरियल होता है। इसके बाद यदि माल आना बंद रहता है तो सप्लाई चेन टूट जाती है। सप्लाई चेन टूटना उद्योग जगत के लिए घातक होता है। इतना नुकसान होता है कि लंबे समय तक उसकी भरपाई करनी होती है। पंजाब के विभिन्न इलाकों से माल आना पूरी तरह बंद हो चुका है। - ***दीपक मैनी, चेयरमैन, प्रोग्रेसिव फेडरेशन आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज***

गाजियाबाद में महंगी हुई पार्किंग फीस, कार-बाइक पर अब कितना लगेगा चार्ज? देखें रेट लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के लोगों को अब पार्किंग फीस के लिए जेब और ढीली करनी होगी। नगर निगम की बृहस्पतिवार को कार्यकारिणी की बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 15 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। नगर निगम की बैठक में पार्किंग फीस बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास हो गया। साइकिल समेत चार पहिया वाहनों की पार्किंग का शुल्क अब दो से चार गुना अधिक होगा।

गाजियाबाद। नगर निगम की बृहस्पतिवार को कार्यकारिणी की बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 15 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इसमें शहर में साइकिल समेत चार पहिया वाहनों की पार्किंग का शुल्क अब दो से चार गुना अधिक होगा।

ये है पार्किंग फीस का नया रेट

पहले नगर निगम की पार्किंग में 12 घंटे तक साइकिल खड़ा करने पर पांच रुपये, दो पहिया वाहन खड़ा करने पर 10 रुपये और चार पहिया वाहन खड़ा करने पर 20 रुपये का शुल्क निर्धारित था, लेकिन अब छह घंटे तक नगर निगम की पार्किंग में साइकिल खड़ा करने पर 10 रुपये, दो पहिया वाहन खड़ा करने पर 20 रुपये और चार पहिया वाहन खड़ा करने पर 40 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। यदि छह घंटे से अधिक वाहन खड़ा रहा तो शुल्क बढ़ जाएगा।

बकाया संपत्ति कर जमा करने पर मिलेगी छूट

जिन करदाताओं पर नगर निगम का संपत्ति कर बकाया है, उनको अब संपत्ति कर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 से मौजूदा वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर जमा करने में दी जा रही छूट की अवधि में भी बदलाव किया गया है, अब अप्रैल से जुलाई माह तक संपत्ति कर जमा करने पर 20 प्रतिशत, अगस्त से सितंबर माह तक संपत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत और अक्टूबर से नवंबर माह तक संपत्तिकर जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलाव यदि करदाता आनलाइन माध्यम से संपत्ति कर जमा करेंगे तो उनको एक प्रतिशत छूट अतिरिक्त मिलेगी।

यह प्रस्ताव भी हुए पास

राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाईटस सोसाइटी के सामने बने गोल चक्कर का नाम देवी अहिल्याबाई होल्कर चौक रखने का प्रस्ताव।

आशियाना पालम कोर्ट सोसाइटी के पास चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौक रखने वहां पर परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जीडीए को प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव

शहर में पानी और सीवर की लाइनों का सर्वे कराने का प्रस्ताव

वैशाली सेक्टर - चार स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव

प्रत्येक वार्ड में पार्षदों व वार्ड की जानकारी देने के लिए दो बोर्ड लगाने का प्रस्ताव

10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से, 46094 छात्र-छात्राएं देंगे एग्जाम; जानें कुछ जरूरी निर्देश

सीबीएसई की कक्षा 10 व कक्षा 12 की परीक्षा आज से शुरू हो रही हैं। पहले दिन वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। अधिकांश छात्र-छात्राओं की परीक्षा 22 फरवरी से अंग्रेजी के प्रश्न पत्र से होगी। परीक्षा के लिए पूरे जिले में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 47 परीक्षा केंद्रों पर 46094 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। छात्रों के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।

गाजियाबाद। सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजूकेशन) की कक्षा 10 व कक्षा 12 की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हो रही हैं। पहले दिन वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। अधिकांश छात्र-छात्राओं की परीक्षा 22 फरवरी से अंग्रेजी के प्रश्न पत्र से होगी। परीक्षा के लिए पूरे जिले में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 47 परीक्षा केंद्रों पर 46094 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे।

इनमें कक्षा 10 के छात्र-छात्राओं की संख्या 25813 और कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं की संख्या 20281 है। पहले दिन कक्षा 12 के तीन पेपर होंगे। एंटरप्रिन्योरशिप और कैपिटल मार्केट ऑपरेशन की परीक्षा का समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा। वहीं फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की परीक्षा होगी। कक्षा 10 में राय, गुरंग तमंग और शेरपा सब्जेक्ट की परीक्षा प्रात 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे होगी। वहीं पेंटिंग की परीक्षा का समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक का होगा।

परीक्षार्थियों को विशेष सलाह

सेंटर पर एक घंटे पहले पहुंचे

रोल नंबर और आइ कार्ड साथ रखें

ज्योमेट्री बाक्स, पेन, पेसिंल,पानी की बोतल साथ रखें

प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा।

काला और नीला पेन ही उपयोग करें।

जिस रायबरेली ने गांधी परिवार को आंखों पर बिठा कर रखा उसे कांग्रेस ने बेगाना कर

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीति से संन्यास ले लेतीं तो उनकी बात समझ में आती, लेकिन हकीकत यह है कि अबकी बार रायबरेली से चुनाव जीतने को लेकर सोनिया गांधी डरी हुई हैं।

अजय कुमार

राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा इसको लेकर बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा अक्सर बदलता रहता है। नेता सहूलियत के हिसाब से अपने वोटरों और जनता से संबंध बनाते-बिगाड़ते हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल हैं सोनिया गांधी। बड़ी बेरुखी के साथ रायबरेली से सोनिया गांधी ने अपना मुंह मोड़ लिया है। जो कृत्य 2019 में उनके बेटे राहुल गाँधी ने अमेठी की जनता की साथ किया था, वही अब 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली की जनता के साथ कर रही हैं। 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने यहां (अमेठी) की जनता से नाता तोड़ लिया, जबकि अक्सर वह अमेठी के लिए ही जीने और मरने की कसमें खाया करते थे। 2019 में मिली हार के बाद राहुल ने अमेठी आना तो दूर, इसका नाम ही लेना छोड़ दिया है। यही काम अब सोनिया गांधी ने किया है। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इस बात का किसी को गिला नहीं है। गिला इस बात का है कि एक बार सोनिया गांधी यहां आकर अपने फैसले से रायबरेली की वोटरों को अवगत तो करा देतीं। आखिर कई लोकसभा चुनावों में यहां की जनता ने सोनिया गांधी के लिए बड़े-बड़े नेताओं को हार का स्वाद चखाने से परहेज नहीं किया था था। आज उन्हीं सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को एकदम से बेगाना कर दिया। इसीलिए यह संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। यदि प्रियंका गांधी के यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना होती तो सोनिया गांधी रायबरेली की

जनता के साथ कतई ऐसा व्यवहार नहीं करतीं। हालांकि अपनी गलती का अहसास होते ही सोनिया गांधी ने एक मार्मिक पत्र रायबरेली की जनता के नाम लिखा जरूर है, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं दिखाई देती है।

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीति से संन्यास ले लेतीं तो उनकी बात समझ में आती, लेकिन हकीकत यह है कि अबकी बार रायबरेली से चुनाव जीतने को लेकर सोनिया गांधी डरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि वह रायबरेली से चुनाव हार जाएंगी, वरना वह पिछली कई बार की तरह इस बार भी यहां नामांकन करके चली जातीं और रायबरेली की जनता उन्हें जिता देती। यदि सोनिया गांधी समेत कोई यह समझता है कि राज्यसभा बीमार लोगों के लिए बनी है तो यह गलत उनकी गलत सोच है।

बहरहाल, रायबरेली की जनता को जिस तरह से सोनिया ने ठेंगा दिखाया है, उसके बाद यदि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ती भी हैं तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल नहीं तो, आसान भी नहीं होगा। बात इतनी ही नहीं है, प्रियंका वाड्रा के लिए मुश्किल इसलिए भी खड़ी हो सकती है क्योंकि लंबे समय से वह रायबरेली से किनारा किए हुए हैं, जबकि वह 2019 तक अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली आया-जाया करती थीं।

गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने 14 फरवरी 2024 को जब राज्यसभा के चुनाव के लिए राजस्थान के जयपुर पहुंच कर पर्चा दाखिल किया था। इसी से साफ हो गया है कि वे इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगी। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। सोनिया गांधी 2019 में यहाँ से पांचवीं बार लोकसभा चुनाव जीती थीं। 2019 के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने घोषणा की थी कि अगला लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वर्ष 1999 में पहली बार वे रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरी और जीती थीं। सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से हटने के बाद प्रियंका गांधी को लेकर दावा किया जा रहा था कि प्रियंका लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उतरेंगी। हालांकि, अब इसको लेकर चर्चा पर विराम-सा लग गया है। कांग्रेस की तरफ से भी चोरी छिपे दावा किया जाने लगा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से 2024 के चुनाव में नहीं उतरेंगी। गांधी परिवार और कांग्रेस को लगता है कि कहीं प्रियंका वाड्रा का भी हाल राहुल जैसा ना हो जाए। जैसे अमेठी की जनता ने राहुल को ठुकरा दिया था, वैसे ही रायबरेली की जनता प्रियंका को ठुकरा दे। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी परंपरागत अमेठी सीट से उतरे थे। यहां से राहुल 2004 से चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन, 2019 में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से राहुल गांधी गिने-चुने मौकों पर ही अमेठी पहुंचे हैं। कांग्रेस इस बार विपक्षी गठबंधन के सहारे यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है जबकि जमीनी स्तर पर पार्टी का संगठन काफी कमजोर है। प्रियंका को यूपी चुनाव 2022 के दौरान प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका ने यूपी की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाई थीं। प्रियंका को इस चुनाव में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के महासचिव पद को संभाल रहीं प्रियंका यूपी में पार्टी के वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाईं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हुए दो-तरफा मुकाबले में पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी।

रायबरेली में पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ती दिखी थी। वहीं, कांग्रेस से भाजपा में आई अदिति सिंह ने रायबरेली सदर सीट से जीत दर्ज की थी। कांग्रेसी किले में पहली बार भाजपा की जीत मिली। 2014 और 2019 के मोदी-योगी लहर में भी रायबरेली का किला फतह करने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस की जमीन पर स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से हुई समीक्षा में सोनिया गांधी के सीट छोड़ने के बाद पार्टी की इस सीट पर जीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए प्रियंका को यहां से नहीं लड़ाया जा रहा है। प्रियंका के करीबी भी दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी स्वयं भी रायबरेली से चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के लिए कोई सेफ सीट नहीं बची है। इसी के चलते करीब 70 सालों के बाद यूपी कांग्रेस विहीन हो जाएगी। जबकि कभी कांग्रेस यूपी का मजबूत गढ़ हुआ करता था। यूपी के बल पर वह केंद्र तक में अपनी सरकार बनती थी। यूपी ने कांग्रेस को कई प्रधानमंत्री दिए थे, लेकिन अब यह सब बातें अतीत के पन्नों में सिमट गई हैं।

होण्डा इस साल भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी 2 जबरदस्त कार , लिस्ट में EV भी शामिल

Honda Elevate आधारित Electric Car के अगले 2-3 वर्षों में लॉन्च होने की उम्मीद है। एलिवेट प्लेटफॉर्म के संशोधित संस्करण के आधार पर भारतीय बाजार के लिए होंडा की पहली ईवी होने वाली है। Honda Amaze को जल्द ही जनरेशन अपडेट मिलने वाला है। होंडा की इस कॉम्पैक्ट सेडान का न्यू जेन मॉडल पहले से डेवलप किया जा रहा है

नई दिल्ली। Honda Cars India ने Elevate SUV के लॉन्च के साथ इंडियन मार्केट में बढ़त हासिल की है। जापानी कार निर्माता कंपनी कारोबार को आगे बढ़ाते हुए साल के अंत तक अपनी पहली Electric SUV के साथ 2 नई कार पेश करने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य साल 2030 तक 5 Electric Cars पेश करना है। आइए, इस साल लॉन्च होने वाली कारों के बारे में जान लेते हैं।

Honda Elevate EV

वर्ष 2030 तक भारत में 5 नई एसयूवी लॉन्च करने की ब्रांड की प्रतिबद्धता के अनुसार,एलिवेट आधारित Electric Car अगले 2-3 वर्षों में लॉन्च होने की उम्मीद है। एलिवेट प्लेटफॉर्म के संशोधित संस्करण के आधार पर भारतीय बाजार के लिए होंडा की पहली ईवी होने वाली है।

अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी का निर्माण कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए भारत में किया जाएगा। Honda Elevate EV आगामी Hyundai Creta EV को सीधी टक्कर देने वाली है और इसका प्रोडक्शन राजस्थान स्थित तापुकरा प्लांट में होगा।

New-Gen Honda Amaze

Honda Amaze को जल्द ही जनरेशन अपडेट मिलने वाला है। होंडा की इस कॉम्पैक्ट सेडान का न्यू जेन मॉडल पहले से डेवलप किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होगी। तीसरी पीढ़ी की Amaze मौजूदा पीएफ2 प्लेटफॉर्म के अपडेटेड वर्जन पर आधारित होगी।

हुड के तहत, मौजूदा 1.2-लीटर आई-वीटीईसी इंजन जो 90 बीएचपी और 110 एनएम पीक टॉर्क उत्पन्न करता है, भारतीय बाजार के लिए बरकरार रखा जाएगा और प्रस्ताव पर कोई डीजल इंजन नहीं होगा। होंडा सेडान की वर्तमान पीढ़ी से प्रेरित एक बिल्कुल नया डिजाइन और अपडेटेड इंटीरियर लेआउट पैकेज का हिस्सा होगा।

Yamaha Ray ZR और Fascino Fi hybrid में आई ये बड़ी दिक्कत, 3 लाख स्कूटर फ्री में बनाकर देगी कंपनी

Ray ZR और Fascino Fi hybrid मॉडल जो इन रिकॉल से प्रभावित हुए हैं उनका प्रोडक्शन पिछले दो वर्षों में किया गया है। इन स्कूटरों को फिर से सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए आवश्यक बदलावों का खर्च यामाहा ही वहन करेगी। दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा है कि वह अपने मालिकों से कोई शुल्क लिए बिना दोषपूर्ण ब्रेक पार्ट्स को बदल देगा।

नई दिल्ली। Yamaha Motor India ने अपने दो पॉपुलर 125 cc स्कूटर- Ray ZR और Fascino Fi hybrid की 3 लाख यूनिट्स रिकॉल की हैं। दोपहिया वाहन निर्माता ने इन मॉडलों में स्थापित दोषपूर्ण ब्रेक पार्ट्स के कारण रिकॉल जारी किया है।

वापस जाएंगी 3 लाख यूनिट

Ray ZR और Fascino Fi hybrid मॉडल जो इन रिकॉल से प्रभावित हुए हैं, उनका प्रोडक्शन पिछले दो वर्षों में किया गया है। इन स्कूटरों को फिर से सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए आवश्यक बदलावों का खर्च यामाहा ही वहन करेगी।

यामाहा मोटर की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जिन स्कूटरों को वापस मंगाया गया है, उनका निर्माण इस साल 1 जनवरी 2022 से 4 जनवरी के बीच किया गया था। दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा कि रिकॉल स्वैच्छिक है और तत्काल प्रभाव से लागू है।

स्कूटरों में आई ये दिक्कत

यामाहा ने यह भी कहा है कि रिकॉल का उद्देश्य Ray ZR और Fascino Fi हाइब्रिड स्कूटरों में दोषपूर्ण ब्रेक पार्ट की समस्या को हल करना है। यामाहा ने कहा कि यह समस्या इन स्कूटरों की वापस ली गई यूनिट के ब्रेक लीवर फंक्शन को प्रभावित करेगी। दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा है कि वह अपने मालिकों से कोई शुल्क लिए बिना दोषपूर्ण ब्रेक पार्ट्स को बदल देगा।

Yamaha ने ग्राहकों से क्या कहा?

यामाहा ने वापस बुलाए गए सभी स्कूटरों के मालिकों से कहा है कि वे पास के यामाहा सेवा केंद्रों या यामाहा की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्विस सेक्शन में जाकर स्कूटर के चेसिस नंबर का उपयोग करके वापस लेने के लिए आवश्यक कदमों की जांच करके वापस बुलाने की पात्रता सत्यापित होगी।

आपको बता दें कि Ray ZR 125 भारत में दो वेरिएंट्स - ड्रम और डिस्क में बेचा जाता है। ड्रम वेरिएंट की कीमत 73,330 रुपये है, जबकि डिस्क ब्रेक वैरिएंट की कीमत 76,330 रुपये है।

Yamaha Fascino 125 को भी दो वेरिएंट- ड्रम और डिस्क में पेश किया गया है। जहां पहले की कीमत 72,030 रुपये है, वहीं दूसरे की कीमत 74,530 रुपये रखी गई है।

ह्युंडई इंडिया भारतीय बाजार में पेश करेगी 4 नई SUVs, लिस्ट में इलेक्ट्रिक कार भी शामिल

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) पूरे कैलेंडर वर्ष 2024 में कई तरह के नए वाहन पेश करने की तैयारी कर रही है। Hyundai Creta का ये परफॉरमेंस बेस्ड वर्जन आने वाले महीनों में शोरूम में आएगा। वहीं Hyundai Tucson के लिए मिड-साइकिल अपडेट कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश किया गया था और ये इस साल भारत में आएगी।

नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) पूरे कैलेंडर वर्ष 2024 में कई तरह के नए वाहन पेश करने की तैयारी कर रही है। इन पेशकशों के बीच, चार नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना है। कंपनी द्वारा आने वाले दिनों में पेश की जाने SUVs में Creta N Line, Alcazar facelift, Tucson और Creta का इलेक्ट्रिक वर्जन शामिल है। आइए, इन अपकमिंग कारों के बारे में जान लेते हैं।

Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta का ये परफॉरमेंस बेस्ड वर्जन आने वाले महीनों में शोरूम में आएगा और कुछ हफ्ते पहले एक विज्ञापन शूट के दौरान इसके स्पाई शॉट सामने आए हैं। इसमें बाहर और अंदर एन लाइन-स्पेसिफिक इनहैंसमेंट मिलता है और ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी। ये पावरट्रेन 160 पीएस और 253 एनएम उत्पन्न करेगा। इसे 6-स्पीड एमटी और 7-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा।

Hyundai Alcazar Facelift

दक्षिण कोरियाई ऑटोमोटिव दिग्गज Alcazar को नया रूप देने की प्रक्रिया में है और इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। क्रेटा एन लाइन के आने के बाद आने वाले महीनों में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। फ्रेस अल्कजार का एक्सटीरियर डिजाइन हाल ही में फेसलिफ्टेड क्रेटा के जैसा होने वाला है। साथ ही इसे क्रेटा के समान इक्विपमेंट लिस्ट और लेवल-2 एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है।

Hyundai Tucson Facelift

Hyundai Tucson के लिए मिड-साइकिल अपडेट कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश किया गया था और ये इस साल भारत में आएगी। अपडेटेड Tucson को रिफ्रेश एक्सटीरियर और इंटीरियर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल में मौजूदा 2.0L पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन को बरकरार रखा जाएगा।

Hyundai Creta EV

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुंडई 2024 के अंत में एक नई मिडसाइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो क्रेटा पर आधारित होगी। इस वाहन के आगामी मॉडल जैसे Maruti Suzuki eVX, इसके टोयोटा समकक्ष, Tata Curvv, Tata Nexon EV और MG ZS EV से कंपीट करने के उम्मीद है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो N, थार और XUV700 पर तगड़ी वेटिंग, जितना बनाते नहीं उससे ज्यादा हो गई बुकिंग!

Mahindra के पास अभी भी ऑर्डर का भारी बैकलॉग है और इस महीने की शुरुआत तक ये 2.20 लाख से अधिक था। महिंद्रा को वर्तमान में हर महीने औसतन 50000 बुकिंग प्राप्त हो रही हैं और मासिक आधार पर उत्पादन लगभग 40000 यूनिट तक बढ़ गया है। XUV700 का बैकलॉग 35000 यूनिट है जबकि थार का बैकलॉग 71000 यूनिट है।

नई दिल्ली। Mahindra & Mahindra हाल के दिनों में अपने प्रोडक्शन में तेजी ला रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह वेटिंग पीरियड को कम करे और अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द वाहन डिलीवर कराए। घरेलू निर्माता के हालिया लॉन्च अत्यधिक सफल रहे हैं। नवीनतम RWD Thar, Scorpio N और XUV700 ने कंपनी को अच्छे नंबर्स दिए हैं।

Mahindra की इन SUVs पर तगड़ी वेटिंग

महिंद्रा के पास अभी भी ऑर्डर का भारी बैकलॉग है और इस महीने की शुरुआत तक ये 2.20 लाख से अधिक था। ब्रांड तेजी से प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए उपाय कर रहा है और नवंबर 2023 से बैकलॉग 60,000 यूनिट से अधिक कम हो गया है। इस दर पर, महिंद्रा 2024 में वेटिंग डिलीवरी समय को काफी कम कर सकता है।

महिंद्रा को वर्तमान में हर महीने औसतन 50,000 बुकिंग प्राप्त हो रही हैं और मासिक आधार पर उत्पादन लगभग 40,000 यूनिट तक बढ़ गया है। Scorpio N और Scorpio Classic ने संयुक्त रूप से प्रति माह 16,000 बुकिंग दर्ज की है और स्कॉर्पियो रेंज को हर महीने मध्यम आकार की एसयूवी बिक्री की टॉप-3 लिस्ट में देखा जाता है।

1 लाख Scorpio N बिकीं

महिंद्रा ने अभी तक स्कॉर्पियो सीरीज की एक लाख से अधिक यूनिट की डिलीवरी नहीं की है, जबकि बोलेरो और बोलेरो नियो ने मिलकर प्रति माह 11,000 बुकिंग हासिल की है, लेकिन डिलीवरी लिस्ट में केवल 10,000 यूनिट लंबित हैं। XUV700 और Thar SUV हर महीने लगभग 7,000 यूनिट की समान बुकिंग संख्या प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन थार का बैकलॉग अधिक है।

XUV700 और Mahindra Thar का भी तगड़ा बैकलॉग

XUV700 का बैकलॉग 35,000 यूनिट है, जबकि थार का बैकलॉग 71,000 यूनिट है। औसतन, Mahindra XUV300 कॉम्पैक्ट एसयूवी और XUV400 EV हर महीने 9,000 यूनिट रिकॉर्ड कर रही हैं और बैकलॉग 9,000 यूनिट के करीब है। कुछ हफ्ते पहले, महिंद्रा ने बिल्कुल नए इंटीरियर और 6 सीटों वाली XUV700 के साथ XUV700 का अपडेटेड वर्जन पेश किया था।

Mahindra का फ्यूचर प्लान

इस कैलेंडर वर्ष के दौरान महिंद्रा ने नए लॉन्च की योजना बनाई है। अगले तीन महीनों के अंदर कंपनी की ओर से XUV300 Facelift पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही 5-Door Thar को भी लॉन्च किया जाना है। वहीं, Mahindra की ओर से XUV700 पर आधारित XUV.e8 इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए दिसंबर 2024 की अस्थायी लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा की जा चुकी है।

किसान आंदोलन से सोनिया के राजस्थान तक

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

पंजाब में तथाकथित किसान आंदोलन पुनः शुरू हो गया है। उसके लिए जिन्होंने भी समय का चयन किया है, उनकी दाद देनी पड़ेगी। चुनाव सिर पर हैं, इसलिए दिल्ली को घेरने की योजना जरूरी थी। लेकिन किनको इस समय जरूरत थी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

हालात देखकर इस बार चुनाव से पहले ही सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश छोड़ गई। अमेठी चाहे छोड़ दी हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिद नहीं छोड़ी। वे सरकार भी बनाएंगे और किसानों की सभी मांगें भी मान लेंगे। वैसे मांगें तो उन्होंने मान ही ली हैं। अब तो काम का दूसरा हिस्सा किसानों को पूरा करना है कि वे उनकी सरकार बना दें। किसान उस पर विचार करते, उससे पहले ही सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ कर राजस्थान चली गईं। राहुल गांधी की सरकार बनने में यह एक अपशकुन हो गया लगता है। लगता है जब तक सरकार नहीं बना लेते, तब तक न्याय यात्रा करते रहेंगे। कभी नहीं रुकेंगे। सरकार बनाने में एक दूसरी बाधा भी आ गई लगती है। बहुत दिनों से राहुल गांधी आशा लगाए बैठे थे कि आम आदमी पार्टी से मिल जाएंगे तो हमारे हिस्से पंजाब और दिल्ली की आधी-आधी सीटें तो आ ही जाएंगी। लेकिन इतने बड़े किसान आंदोलन के बीच में ही केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की औकात तो एक सीट की भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक सीट दे देंगे। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, वहां सारी सीटें आम आदमी पार्टी को ही लडनी हैं'

पंजाब में तथाकथित किसान आंदोलन पुनः शुरू हो गया है। उसके लिए जिन्होंने भी समय का चयन किया है, उनकी दाद देनी पड़ेगी। चुनाव सिर पर हैं, इसलिए दिल्ली को घेरने की योजना जरूरी थी। लेकिन किनको इस समय जरूरत थी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाहिर है यह जरूरत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा थी। पिछली बार जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के मुख्यमंत्री ने बहुत ही चालाकी से आंदोलन को दिल्ली के दरवाजे पर धकेल दिया था। केवल धकेल ही नहीं दिया था बल्कि परोक्ष रूप से उसकी सब प्रकार से सहायता भी की थी। अंग्रेजी वाले जिसको लोजिस्टिकल फैसलिटीज कहते हैं, वे सभी मुहैया करवाई। आन्दोलन से कांग्रेस को कोई फायदा हुआ या नहीं, यह तो वही जानती होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री अति उत्साह में था उसका जरूर उत्साह भंग हो गया। अब मोहरे बदल गए हैं। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गद्दी पर है। लेकिन उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल अत्यंत संकट में हैं। ईडी ने उन्हें दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में पांचवीं बार समन किया है। इस जांच में केजरीवाल के तीन साथी सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय बाबू पिछले लम्बे अरसे से जेल में हैं। जमानत के लिए हाथ-पैर मारते रहते हैं, लेकिन नसीब नहीं होती। जरूर कोई पुख्ता सबूत रहे होंगे। अब शायद वही सबूत केजरीवाल की ओर झांक रहे होंगे। इसलिए ईडी उन्हें बार-बार बुला रही है, लेकिन वे उसके सामने जा नहीं रहे।

उनका कहना है कि उन्हें देश में अस्पताल और स्कूल खोलने हैं। इसलिए उनके पास समय कहां है। इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि पंजाब से ज्यादा से ज्यादा किसान जाकर दिल्ली को घेर लें। दिल्ली ही तो शराब को लेकर केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पंजाब का मुख्यमंत्री दहाड़ रहा है। वह हरियाणा सरकार को कोस रहा है। पंजाब के किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अब वह पंजाब की एयर स्पेस को लेकर भी सक्रिय है। पंजाब के आकाश में हरियाणा का ड्रोन क्यों? कल हो सकता है वह अपनी पुलिस को इसी काम में लगा दे कि पंजाब का ड्रोन हरियाणा के आकाश में दिखाई दे तो चुनिए गिरा लिया जाए। इससे सिद्ध हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसान के पक्ष में है। बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री यह भी आगाह कर रहे हैं कि कल लोकसभा राष्ट्रगीत में से पंजाब को भी निकाल सकती है। आम आदमी पार्टी अब इस प्रकार के मुद्दों की तलाश में निकल पड़ी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को ललकार रही है। दिल्ली जाने के रास्ते में जो बाधा हो, उसको हटाओ। इस काम में चोट वगैरह लग जाए तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। शायद केजरीवाल को लगता होगा कि शराब का जो मामला पीछा नहीं छोड़ रहा, शायद उसको दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान ही छुड़ा दें। शेष बात रही किसानों की मांगों की। कोई भी मसला हो उसे बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। जब सरकार बातचीत करना चाहती है तो सडक़ों पर निकल आना और रास्ते अवरुद्ध कर देना शायद उचित नहीं है। किसानों को सरकार से बातचीत करनी चाहिए। अलबत्ता राहुल गांधी ने अवश्य किसानों से वादा किया है कि जब 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वे किसानों की सभी मांगें स्वीकार कर लेंगे। राहुल गांधी किसानों की इतनी भीड़ देख कर सरकार आने का गणित बिठा ही रहे थे, इसी बीच पता चला कि उनके माता जी, कभी कांग्रेस के गढ़ रहे उत्तर प्रदेश को त्याग कर राजस्थान चली गईं। वे वहां से संसद में आना चाहती हैं। यकीनन आ भी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में लम्बे अरसे से मां-बेटा अमेठी और रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे। जीत भी जाते थे। इन्हीं दो सीटों पर पंजे की छाप दिखाई देती थी। लेकिन पिछले चुनाव में राहुल गान्धी उत्तर प्रदेश छोड़ कर केरल चले गए। उन्हें पूरी आशा थी कि अमेठी वाले अब नहीं मानेंगे। इसलिए वे समय रहते केरल चले गए। अमेठी वालों ने सचमुच राहुल जी की आशा पर फूल चढ़ा दिए। वे वहां से हार गए।

हालात देखकर इस बार चुनाव से पहले ही सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश छोड़ गई। अमेठी चाहे छोड़ दी हो, लेकिन राहुल गान्धी ने जिद नहीं छोड़ी। वे सरकार भी बनाएंगे और किसानों की सभी मांगें भी मान लेंगे। वैसे मांगें तो उन्होंने मान ही ली हैं। अब तो काम का दूसरा हिस्सा किसानों को पूरा करना है कि वे उनकी सरकार बना दें। किसान उस पर विचार करते, उससे पहले ही सोनिया गान्धी उत्तर प्रदेश छोड़ कर राजस्थान चली गईं। राहुल गान्धी की सरकार बनने में यह एक अपशकुन हो गया लगता है। लगता है जब तक सरकार नहीं बना लेते तब तक न्याय यात्रा करते रहेंगे। कभी नहीं रुकेंगे। सरकार बनाने में एक दूसरी बाधा भी आ गई लगती है। बहुत दिनों से राहुल गान्धी आशा लगाए बैठे थे कि आम आदमी पार्टी से मिल जाएंगे तो हमारे हिस्से पंजाब और दिल्ली की आधी-आधी सीटें तो आ ही जाएंगी। लेकिन इतने बड़े किसान आन्दोलन के बीच में ही केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की औकात तो एक सीट की भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक सीट दे देंगे। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, वहां सारी सीटें आम आदमी पार्टी को ही लडनी हैं। वहां शायद कांग्रेस की एक सीट की भी औकात नहीं है। लेकिन राहुल गान्धी के सरकार बनाने के चुटकुलों की ओर ध्यान न भी दें, तब भी आखिर यह तो देखना परखना होगा ही कि किसान आन्दोलन के पीछे कौन है और कहां है? आखिर किसान सरकार से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? किसानों को सरकार से भिड़ा कर कौन अपने व्यक्तिगत हितों की साधना कर रहा है? सवाल यह भी है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस किसानों से किए वादे कैसे निभाएगी, जबकि पहले किए गए सभी वादे उसने पूरे नहीं किए हैं।

संपादक की कलम से

अरब में 'नमो नारायण'

संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में हिंदू मंदिर बना है। यह दुनिया के किसी अजूबे, करिश्मे और अभूतपूर्व मिसाल से कम नहीं है। इसके गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थ भी हैं, जिन्हें दुनिया पढ़ेगी और समझेगी। अरब के इस्लामी देश अमूमन कट्टरपंथी, धार्मिक तौर पर संकीर्ण और असहिष्णु माने जाते रहे हैं। यह मंदिर उन धारणाओं को खंडित करता है। अबू धाबी शहर के मरुस्थल में बने हिंदू मंदिर में मिस्र, एजटेक, अफ्रीकी, यूरोपीय और चीनी सभ्यताओं के प्रतिचिह्न भी हैं और कहानियां भी हैं। कुरान को भी देखा जा सकता है। जो 'वॉल ऑफ हॉरमोनी' बनाई गई है, वह सर्वधर्म समभाव का दुर्लभ उदाहरण है। वोहरा समुदाय के मुसलमानों ने उसमें योगदान दिया है। हिंदू के अलावा बौद्ध, जैन, ईसाई संप्रदायों की प्रतिमाएं भी हैं। यकीनन यह मंदिर अध्यात्म और आस्थाओं का सामंजस्य है, सह-अस्तित्व का बेजोड़ नमूना है। करीब 27 एकड़ भूखंड के आधे भाग में बनाए गए मंदिर के लिए संयुक्त अरब अमीरात के इस्लामी शासक, राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद ने जमीन दान में दी और अरब देश में हिंदू स्वामीनारायण मंदिर बनाने की इजाजत भी दी। इससे व्यापक सहिष्णुता और धार्मिक उदारता और क्या हो सकती है? महत्वपूर्ण यह भी है कि हिंदू मंदिर बनाने का न तो कोई विरोध किया गया और न ही कोई दंगा-फसाद भडक़ा। किसी अन्य अरब देश ने भी आपत्ति नहीं की। असल में यही धर्मनिरपेक्षता है। मंदिर के सात शिखर सात महत्वपूर्ण भगवानों को समर्पित हैं। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, भगवान स्वामीनारायण, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सात शिखर अरब के सात अमीरात के भी प्रतीक हैं। हिंदू मंदिर में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों को प्रतीक-रूप में बनाया गया है। समुद्री जहाजों से पवित्र नदियों के जल अबू धाबी में लाए गए और अब वही जल इन प्रतीकात्मक नदियों में प्रवाहित हो रहा है। मंदिर के आंगन में वाराणसी का घाट भी बनाया गया है।

ऐसे बिम्बात्मक भारत की कल्पना हमने तो कभी नहीं की थी। मंदिर में खासतौर पर 96 घंटियां बनाई गई हैं। घंटियां हमारे मंदिर की सार्थक पहचान होती हैं। मंदिर को देखें, तो 'लघु हिंदुस्तान' प्रतीत होता है। मंदिर परिसर में एक 'दैवीय आंख' भी बनाई गई है, जिसके जरिए क्या देखा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बने मंदिर में सफेद संगमरमर, राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर का ही प्रयोग किया गया है। नागर शैली में बनाए गए मंदिर में कोई लोहा, इस्पात जैसी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के 402 स्तंभों पर जो मूर्तियां, पशु-पक्षी, जानवर उकेरे गए हैं, उस नक्काशी का वर्णन एक आलेख में नहीं किया जा सकता। मेजबान देश को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं में हाथी, ऊंट और शेर जैसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जानवरों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय पक्षी बाज को भी स्थान दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक अरब, इस्लामी देश में हिंदू मंदिर बनाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। यह हमारे देश के लिए गरिमापूर्ण सम्मान है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जिस तरह प्राण-प्रतिष्ठा की गई, उसी तरह मंत्रोच्चार और आरती के साथ अबू धाबी के इस मंदिर में भी प्राण-प्रतिष्ठा की गई। दरअसल यह मंदिर भारत-अमीरात की प्राचीन दोस्ती की मिसाल है। यह अरब देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। करीब 39 लाख भारतीय यहां बसे हैं और काम कर रहे हैं। अमरीका, सऊदी अरब, नेपाल के बाद संयुक्त अरब अमीरात चौथा देश है, जहां इतनी बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं। आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों के अलावा आध्यात्मिक आत्मीयता और सहिष्णुता ज्यादा मायने रखती है।

राय

हिमाचल से राज्यसभा

राज्यसभा में कांग्रेस के कंधे मजबूत कर रहा हिमाचल अपने लिए एक वकील भी चुन रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच से इस बार राज्यसभा की पैरवी में, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। हिमाचल में सत्ता के लाव लश्कर पहले ही आलाकमान की खुशामद में राज्यसभा के दरवाजे ढूंढ रहे थे और अंततः एक नाम मिल गया, मनु सिंघवी। इसमें दो राय नहीं कि सिंघवी के जरिए कांग्रेस का राज्यसभा में रुतबा और बहस का जज्बा परिलक्षित होगा। सिंघवी की पैरवी में कांग्रेस की अदालती पहुंच व तकरीर बढ़ जाती है। कई कारण रहे होंगे जिनके तहत यह केंद्रीय नेता हिमाचल की सीट पर अधिकार पा रहा है, लेकिन प्रदेश की संभावनाओं में राज्यसभा का कद असमंजस में रहा है। हालांकि हिमाचल से राज्यसभा गए नेता भी कुछ खास नहीं कर पाए। वर्षों तक राज्यसभा में रहे विप्लव ठाकुर व आनंद शर्मा प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का परचम ऊंचा नहीं कर पाए और इसी तरह प्रो. सिकंदर भी एक आजमाइश की तरह दिखाई देते हैं। यह दीगर है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में राज्यसभा की पुकार सुन रहे थे। आशा कुमारी, ठाकुर कौल सिंह, राम लाल ठाकुर के अलावा कई अन्य चेहरे भी इस उम्मीद में थे कि किसी तरह राज्यसभा का रास्ता अख्तियार करें, लेकिन राजनीति की वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का अपना रास्ता और अपना चुनाव है। यही चुनाव राज्यों में सत्ता की तलाश में कहीं अंगुली पकड़ता है, तो कहीं अंगुली मरोड़ता है। मनु सिंघवी के नाम पर लगी मोहर कम से कम यह तो साबित कर गई कि हिमाचली सत्ता की हर चाबी आलाकमान के पास है, वरना कई राज्यों के नेताओं की फितरत में पार्टी के वजूद को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा के टिकट इस बार शीर्ष तक को छांव दे रहे हैं, तो जमीन की पैमाइश अब लोकसभा चुनाव में नई परख के साथ होगी। राज्यसभा के उम्मीदवार को कांग्रेस के कुल चालीस वोट काम आएंगे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह इश्तिहार कोई गारंटी नहीं। भले ही भाजपा अपने 25 विधायकों की शुमारी में हिमाचल विधानसभा का कमजोर पक्ष है, लेकिन चुनाव की परिपाटी में यह पार्टी चौबीस घंटे काम करती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि पार्टी अपनी भुजाओं पर उम्मीदवारी का दावा कर रही है। केंद्र की झोली में एक सांसद डाल कर सुक्खू सरकार की हैसियत में इजाफा लाजिमी है, लेकिन हिमाचल के मतदाता के समक्ष अब मुख्यमंत्री को अपना रुतबा दिखाना है। राजनीति के पंडित तो सत्ता के दम पर, हिमाचल के नतीजों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की परीक्षा मान रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के संकल्प और संबोधन भी सुने जाएंगे। हिमाचल में चुनावी बाजी पलटने की प्रथा ने कांग्रेस को सत्ता और सत्ता को एक सांसद दे दिया। अब सरकार को लोकसभा के चार सांसद देने का रास्ता अख्तियार करना है। जो कल विधायक बने थे, उन्हें अब उसी भावना से सांसद के पक्ष में अपनी सफलता दोहरानी है। सरकार की मशीनरी और सरकार के फलक पर छाए मंत्री, कैबिनेट रैंक के नेता व संगठन की चमक से लोकसभा चुनाव की तस्वीर बनानी होगी। राज्यसभा के लिए हिमाचल की सत्ता के आंकड़े दुरुस्त हैं, लेकिन अब संगठन के साथ आंकड़े सही करने की शर्त है। क्या हिमाचल में सत्ता और संगठन एक व एकजुट हैं।

भूपिंदर सिंह

अब सुक्खू सरकार बनाएगी खेल नीति

प्रतिभा खोज के बाद पढ़ाई के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिएं। इसके लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की तर्ज पर अपना राज्य क्रीड़ा संस्थान हो, वहां पर प्रदेश के खिलाडिय़ों को लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगें'

अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नई खेल नीति लाएगी जिससे खिलाडिय़ों को अधिक लाभ होगा। इससे पहले पिछली भाजपा सरकार ने भी राज्य के लिए नई खेल नीति बनाई थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फिर खेल नीति पर चर्चा शुरू हो गई है, मगर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाडिय़ों को नगद ईनाम अभी तक नहीं मिला है। हिमाचल की राजधानी शिमला में 16 मई 2023 को प्रदेश सरकार के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य के खेल संघों के साथ बैठक कर खेल उत्थान के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें नई खेल नीति के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में खेल आरक्षण को तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने की बातें प्रमुख रही थी। पिछली भाजपा सरकार के पांच सालों से हिमाचल प्रदेश में खेल नीति को नया स्वरूप देने की बात चलती रही थी। अंतिम साल में नई खेल नीति को मंत्रिमंडल की बैठक में कानूनी जामा पहनाया गया, मगर इसको जमीन पर उतारने से पहले सरकार का कार्यकाल ही खत्म हो गया।

अब सरकार कांग्रेस की है और विक्रमादित्य के बाद यादविंद्र गोमा उसमें खेल मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढांचा तो बन कर तैयार हो चुका है, मगर प्रशिक्षकों व अन्य सुविधाओं के अभाव में वहां पर उस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी खेल संस्कृति का अभाव साफ देखा जा सकता है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सरकार में बनी खेल नीति में हिमाचल के खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत आरक्षण बहुत बड़ी सौगात है। अब दो दशक बाद विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा कर बनी नई खेल नीति में खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पदक विजेता खिलाडिय़ों की नगद ईमानी राशि को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना भाजपा सरकार का बहुत अच्छा कदम रहा है। केन्द्र व केरल सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में पहली बार पदक विजेता खिलाडिय़ों के प्रशिक्षकों को भी नगद ईमानी राशि देने की बात की गई है। वर्तमान खेल मंत्री की तरह ही पिछली भाजपा सरकार में तत्कालीन खेल मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में धर्मशाला के मिनी सचिवालय में नई खेल नीति के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों व खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक हुई थी। इस बैठक में खेल उत्थान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई थी। इसके बाद भी खेल मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न खेल संघों से मिल कर लंबी चर्चा कर नई खेल नीति के लिए व्यावहारिक पहलुओं तक जाने की सोची थी, मगर कोरोना के दोबारा कहर से वह सब नहीं हो पा रहा था। इसके बाद अब खेल विभाग के अधिकारी व खेल के जानकार खेल नीति को नए स्वरूप तक ले जाने के लिए संघर्षशील हो गए और देर बाद ही सही, हिमाचल प्रदेश को अब नई खेल नीति मिल गई है, मगर जब तक धरातल पर कार्य नहीं होगा आप फिर चाहें कागजों में कई बार नई खेल नीति बनाते रहें।

खेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इससे जब हजारों विद्यार्थी फिटनेस कार्यक्रम से गुजरेंगे तो उनमें कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। खिलाडिय़ों से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन के लिए राज्य में अधिक से अधिक खेल अकादमियां व शिक्षा संस्थानों में खेल विंग, स्थान की सुविधा व प्रतिभा को देखते हुए सरकारी व खेल संघों के माध्यम से खोलने की बात को अमलीजामा पहनाया जाए। अवार्डी व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाडिय़ों को पेंशन योजना का भी प्रावधान किया गया है, तो उन्हें उनका हक दो। खेल नीति में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण व प्रतियोगिता के लिए विशेष अवकाश की बात है, क्या ऐसा हो पाता है? खेलों के लिए प्रेरित कर खेल मैदान तक ले जाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल व कालेज स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात तो खेल नीति में कही गई है, मगर हकीकत सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न खेलों का स्तर राज्य में खेल छात्रावासों के खुलने के बाद भी अभी तक सुधरा नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ जुनूनी प्रशिक्षकों के बल पर कभी-कभी अच्छे परिणाम दे पाया है हिमाचल प्रदेश, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक खेलों को छोड़ कर अधिकांश बार पिछड़ा ही रहा है। हिमाचल हो या देश का कोई अन्य राज्य, उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए केवल प्रशिक्षक ही मुख्य किरदार दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत का खेल मंत्रालय व कई राज्य भी अपने यहां हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर जोर दे रहे हैं तथा वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले प्रशिक्षकों को अनुबंधित कर रहे हैं। खेलो इंडिया, गुजरात व पंजाब के उच्च खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिक से अधिक इस तरह के हाई परफॉर्मेंस केंद्र व अकादमी खोलनी होंगी।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन करवाने वाले अनुभवी प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने की शर्तों पर पांच वर्षों के लिए अनुबंधित करना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की संतानों को भी हिमाचल प्रदेश में रह कर ही वह प्रशिक्षण सुविधा मिल सके। आप हर विद्यार्थी को फिटनेस के लिए खेल मैदान में ले जाएंगे, उनमें से जरूर कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। प्रतिभा खोज के बाद पढ़ाई के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिएं। इसके लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की तर्ज पर अपना राज्य क्रीड़ा संस्थान हो, वहां पर हिमाचल प्रदेश के खिलाडिय़ों को वैज्ञानिक आधार पर लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगें तथा प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों व पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों के लिए सेमिनार व कम अवधि के प्रशिक्षक बनने के कोर्सेज हों। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व लगने वाले कोचिंग कैम्प भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि पहाड़ के लोगों को भी वही सुविधा उपलब्ध हो जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जा सकें।

हास्य रस

वसंत का जादू

वसंत पंचमी के दिन सुबह-सुबह ही आया था वसंत। आया और चुपचाप खड़ा हो गया।

उसके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, पीले परिधान में लिपटा, हाथों में फूल थामे वह मुझे घूर रहा था। मैं ही बोला- 'तुम वसंत ही हो न?' उसकी मुस्कान फैल गई और वह बोला-'सही पहचाना कवि महाराज। कैसे चुपचाप बैठे हो। मेरा स्वागत करो। मैं प्राणी मात्र से लेकर प्रकृति में नव संचार करने वाला हूं। उठो, उत्साह से गले लगाओ मुझे। मैं सबसे पहले तुम्हारे ही आया हूं।' मैंने मुंह फेर लिया और अनमने भाव से बोला-'यहां क्यों आए हो ऋतुराज। देख नहीं रहे, सारे गमले सूख गए हैं। मेरे पास इनमें पानी देने तक का वक्त नहीं है। मैं गृहस्थी की गाड़ी में कोल्हू के बैल की तरह घूम रहा हूं। मेरी धमनियों का रक्त जम गया है, तुम नव संचार क्या करोगे?' वसंत प्रफुल्लता से भरा हुआ था, बोला-'छोड़ो सारी चिंताएं। मैं तुम्हारे भीतर भर दूंगा उत्साह और उमंग। परेशानियों से घबराने से हालात नहीं बदलेंगे कविजी। कोई मस्ती का गीत लिखो और गाओ उसे पूरे तरन्नुम के साथ, तुम ही निराश हो जाओगे तो फिर यह जगत मिथ्या है, मेरा स्वागत करने वाला फिर है कौन?' 'लेकिन मैं क्या कर सकता हूं वसंत। देख नहीं रहे उत्साह और उमंग से बंटता क्या है? मैं अजीब भंवरजाल में फंसा हुआ हूं। किसी अमीर के दस्तक देते तो तुम्हारा काम बन जाता। तुमने गलत घर चुन लिया है ऋतुराज। अभी भी वक्त है, जाओ किसी सदाबहार फुलवारी में, वहां तुम्हें हार्दिक प्रसन्नता होगी। दरअसल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। न पीले परिधान और न पीले चावल।

मेरे पास तो पीले दांत हैं, जो अब हंसने के भी काम नहीं आते।' मैंने वसंत को वास्तविकता से परिचित कराने को कहा तो भी वह विहंसता रहा और बोला-'अब छोड़ो भी सारी नाराजी। वर्ष में एक बार आता हूं। मैं मांगता क्या हूं तुमसे। बस यही तो मांगता हूं कि तुम खुश रहो तो मेरा आना सार्थक हो जाए। गत वर्ष भी तुम उदास और नाराज थे। वही हाल इस वर्ष में है। खेतों में लहलहाती सरसों को देखो, गेहूं की बालियों का इठलाना और भंवरे का गुनगुनाना, क्या तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? कवि उठो, मेरे साथ चहलकदमी करो, तुम्हारी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा।' मैं पलटकर बोला-'मेरे जीवन में वसंत नहीं है प्यारे वसंत। मेरी पीड़ाओं का अंत भी नहीं होगा। मैं टोटे की लड़ाई में उलझा हूं। मेरे अभाव गिनाऊंगा तो तुम कहोगे मैं वसंत में कैसी बातें कर रहा हूं। मेरे पास एक अदद कुर्सी भी नहीं है, जिस पर तुम्हें बैठ जाने की कहूं।' वसंत ने फिर मुझे समझाना चाहा-'मुझे कुरसी नहीं चाहिए कवि महाराज। मुझे तुम्हारी कुशलता और खुशहाली चाहिए। जीवन का यही होता है वसंत। निराशा को त्यागो और भीतर मन में भर लो हजारों उमंगें। अभाव तो पूरे जीवन का रोना है। पीले दांतों से ही सही, मगर हंसो तो सही। मन की कालिख को धो डालो। मैंने कहा न, उठो और चलो मेरे साथ खेत-खलियानों में, जहां मैं वसंती पवन के झोंकों के साथ नाच रहा हूं। तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुमने प्रकृति से दूर रहकर अपने तनाव बढ़ा लिए हैं। मैं तनाव मुक्ति की दवा नहीं, हवा हूं। मुझे महसूस करोगे तो तुम्हारे सूखे जीवन में भी लौट आएगी हरियाली। गमले के ये पौधे फिर से खिल उठेंगे।' इस बार मुझे लगा-मेरे मन में आशाओं का नव संचार होने लगा है और यह वसंत सच ही तो कहता है।

वह हमसे लेता क्या है? वह तो देने आता है ढेरों खुशियां, उल्लास और उमंग। मेरे होठों पर हंसी आई और मैं वसंत से बोला-'मैं नासमझ हूं वसंत। दुनियादारी के पचड़ों ने मुझे तुम्हारे अहसास तक को भुला दिया था। मैं संवेदनाशून्य हो गया हूं। जड़वत हो जाने से मैं नहीं सोच पाता कि तुम मेरे लिए खुशियां लेकर आए हो। मैं फिर लिखूंगा नई कविताएं और गाऊंगा उन्हें पूरी लय के साथ।' वसंत ने दौडक़र मुझे बाहों में भर लिया और एक पल को मैं बेसुध सा होकर खुशियों से पगला सा गया। वसंत ने अपना जादू चला दिया था। वसंत का जादू यही तो होता है, बाकी तो सब बेकार है। मैं मदहोशी में डूब गया था। वसंत मेरे पोर-पोर में नाच रहा था।

पूरन सरमा

इनसाइड

सस्ता सोना खरीदने का आज है आखिरी मौका, जानें कहां और कैसे खरीद सकते हैं गोल्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने के लिए Sovereign Gold Bond Scheme शुरू की गई है। आज इस स्कीम की फरवरी सीरीज का आखिरी दिन है। यानी कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) खरीदने का सोच रहे हैं तो आप सस्ते में केवल आज ही खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड का प्राइस क्या है?

नईदिल्ली। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करने का केवल आज का ही दिन बचा है। बता दें कि भारत सरकार ने एसजीबी की फरवरी सीरीज 12 फरवरी 2024 से शुरू की थी, जो आज (16 फरवरी 2024) को बंद हो जाएगी। इसमें आपको बाजार दर से कम कीमत पर गोल्ड खरीदने का अवसर मिलता है।

क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत

बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इश्यू प्राइस 6,263 प्रति ग्राम तय की गई है। इस कीमत पर इसे आप केवल आज ही खरीद सकते हैं। हालांकि, यह गोल्ड बॉन्ड 21 फरवरी 2024 को जारी होगी।

अगर आप इस बॉन्ड को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपको गोल्ड बॉन्ड के लिए केवल 6,213 रुपये का भुगतान करना होगा।

आप कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं और अधिकतम 4 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं।

सॉवरेन गोल्ड पर कितना ब्याज मिलता है

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी टेन्योर 8 साल होती है। इसे आप वैसे 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। बता दें एसजीबी में 2.50 फीसदी के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलता है।

आप गोल्ड बॉन्ड को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसे आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के जरिये भी खरीद सकते हैं।

इसे आप इसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई पर बेच सकते हैं।

रेलवे के खाने को लेकर संसदीय समिति ने क्यों जताई नाराजगी?

इंडियन रेलवे रिपोर्ट में कहा गया है कि "नीति में बार-बार बदलाव और खानपान इकाइयों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी से रेलवे कौ और फिर आईआरसीटीसी को सौंपे जाने से यात्रियों को दी जाने वाली खानपान सेवाओं के प्रबंधन में अनिश्चितता की स्थिति बन गई।" अधीर रंजन चौधरी की अध यक्षता वाली समिति ने रेलवे की खानपान नीति और ट्रेनों में भोजन सेवाओं पर इसके प्रभाव की विस्तृत जांच की।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे सबसे सुगम साधन माना जाता है। देश में हर दिन लगभग 2.5 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं। अगर लंबी दूरी की यात्रा में शानदार खाना भी मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन रेलवे के खाने की अक्सर आलोचना होती है और ज्यादातर लोग इसकी शिकायत ही करते हैं। हालांकि प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी और अब वंदे भारत में मिलने वाले खाने की कई लोग तारीफ भी करते हैं लेकिन ज्यादातर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं।

अब एक संसदीय समिति ने भी रेलवे के खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। लोक लेखा समिति ने हाल ही में लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे की खानपान नीति में बार-बार बदलाव और मौजूदा नीति के कार्यान्वयन में कई विसंगतियों के कारण भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और साफ-सफाई से समझौता हो रहा है।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने रेलवे की खानपान नीति और ट्रेनों में भोजन सेवाओं पर इसके प्रभाव की विस्तृत जांच की। 'भारतीय रेलवे में खानपान सेवा'

(Catering Service in Indian Railways) नाम से पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 की नीति में आईआरसीटीसी को सौंपी गईं और फिर 2010 की नीति के अनुसार जोनल रेलवे को हस्तांतरित कर दी गईं कई गतिविधियां 2017 की नीति में फिर आईआरसीटीसी को वापस सौंप दी गईं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, ''नीति में बार-बार बदलाव और खानपान इकाइयों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी से रेलवे कौ और फिर आईआरसीटीसी को सौंपे जाने से यात्रियों को दी जाने वाली खानपान सेवाओं के प्रबंधन में अनिश्चितता की स्थिति बन गई।''

रिपोर्ट में कही गई मुख्य बातें

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005 से 2017 के बीच रेलवे की खानपान नीति में कई बदलाव किए गए। इस दौरान कैटरिंग गतिविधियों को आईआरसीटीसी से जोनल रेलवे को, फिर वापस आईआरसीटीसी को सौंपने जैसे फैसले लिए गए।

रेलवे की विभिन्न जोनल इकाइयों द्वारा अपनी मर्जी से नीतिगत बदलाव किए जाने की भी रिपोर्ट में आलोचना की गई। इससे अलग-अलग ट्रेनों में खानपान व्यवस्था की गुणवत्ता में असमानता पैदा हुई।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में पैंट्री कार नहीं होने से भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई। कई मामलों में भोजन को रास्ते में लंबे समय तक रखा जाता है, जिससे स्वच्छता संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं।

रिपोर्ट में पाया गया कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनधिकृत विक्रेताओं की मौजूदगी भी भोजन की गुणवत्ता और यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

समिति ने की ये सिफारिशें

रेलवे की खानपान नीति में स्थिरता लाने की जरूरत है। लगातार हो रहे बदलावों से कैटरिंग कंपनियां लंबे समय के लिए निवेश से बचती हैं, जिसका असर खाने की गुणवत्ता पर पड़ता है।

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। सभी कैटरिंग सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस और नियामक मानकों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए।

अनधिकृत विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ट्रेनों एवं स्टेशनों पर उनकी मौजूदगी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

रेलवे यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

बताए गए मुद्दों का नहीं हुआ समधान तो ये होगा असर

रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का अगर समाधान नहीं किया गया तो यात्रियों को घटिया और अस्वच्छ खाना ही मिलता रहेगा।

खानपान सेवाओं में भ्रष्टाचार से रेलवे को आर्थिक नुकसान हो सकता है और यात्रियों का भरोसा कम हो सकता है।

भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार से रेलवे यात्रा को अधिक सुखद और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

अब क्या हो सकता है आगे?

रेल मंत्रालय को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए और उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

रेल यात्रियों को भी जागरूक होना चाहिए और खराब खानपान सेवाओं की शिकायत संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए।

भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार के लिए रेलवे, कैटरिंग सेवा प्रदाता और यात्री समुदाय को मिलकर काम करना होगा।

फिर अपडेट हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल की कीमत

रोजाना सुबह सरकारी और निजी तेल कंपनियां सभी छोटे और बड़े शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट करती है। आज भी इनके नए दाम जारी हो गए हैं। मई 2022 से इनकी कीमतों पर रष्ट्रीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि वैट की वजह से कई शहरों में इनके रेट बदलते रहते हैं। जानिए आपके शहर में क्या है तेल की कीमत।

नई दिल्ली। शुक्रवार 16 फरवरी को तेल कंपनियों ने हर छोटे और बड़े शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट कर दिया है। ऐसे में गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करने चाहिए। चलिए, जानते हैं कि आप आपके शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत क्या है?

राजधानी समेत अन्य महानगरों में क्या है तेल की कीमत?

गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक आज तेल की कीमतें इस प्रकार हैं:

नई दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

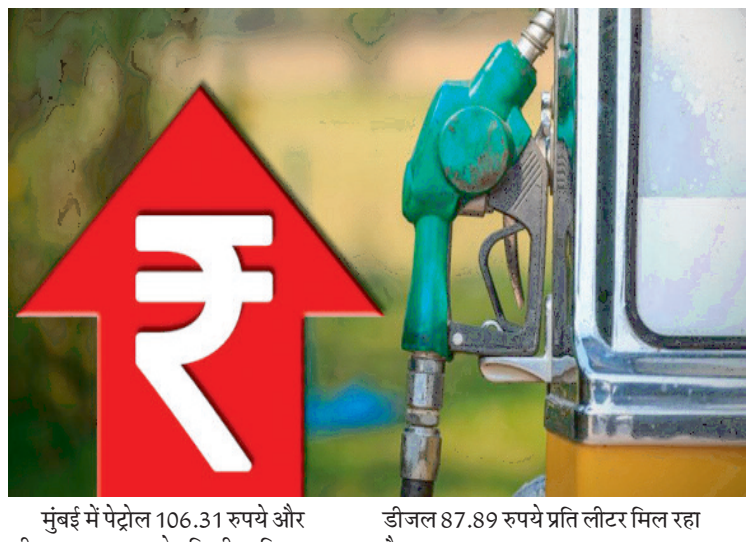

मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

एनसीआर सहित अन्य शहरों में क्या है रेट?

नोएडा में पेट्रोल 97.00 रुपये और डीजल 89.65 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

गुरुग्राम में पेट्रोल 96.77 रुपये और डीजल 89.65 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

लखनऊ में पेट्रोल 96.47 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

रोज मैसेज पर पता चलेगा लेटेस्ट रेट

बता दें कि इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों के रोज पेट्रोल-डीजल के रेट की जानकारी मैसेज पर देता है। इसके लिए कस्टमर अपने फोन से RSP <स्पेस> पेट्रोल पंप का कोड डायल करके 92249 92249 पर मैसेज करना होता है। इसके बाद उन तक तेल की अपडेटेड कीमतों का मैसेज भेज दिया जाता है।

NPS Account हो गया है फ्रीज, इन स्टेप को फॉलो कर एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट

रिटायरमेंट के बाद पेंशन इनकम को जारी रखने में काफी मदद करता है। सरकार ने पेंशन के लिए कई स्कीम शुरू की है। इन स्कीम में से एक एनपीएस है। इसमें बुढ़ापे के बाद पेंशन और 60 वर्ष की आयु में 60 फीसदी निवेश की राशि भी मिलती है। अगर आपका एनपीएस अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आप इन तरीकों से उसे एक्टिव कर सकते हैं।

नई दिल्ली। बुढ़ापे में भी इनकम जारी रखने में पेंशन काफी अहम रोल निभाता है। रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए कई लोग जॉब के शुरुआत से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं।

वर्तमान में निवेश के लिए कई स्कीम मौजूद है। इनमें से एनपीएस (National Pension System-NPS) एक है।

इसमें खाताधारक को रिटर्न का लाभ मिलता है। इसके अलावा मैच्योरिटी के बाद पेंशन की सुविधा भी मिलती है। जब निवेशक की आयु 60 साल की हो जाती है तो वह एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है।

वहीं, 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एनपीएस बुढ़ापे के लिए मोटे फंड के साथ पेंशन का भी इंतजाम कर देता है।

बता दें कि अगर निवेशक एक पूरे वित्त वर्ष में एनपीएस अकाउंट में न्यूनतम राशि नहीं डिपॉजिट करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। निवेशक को एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना चाहिए।

फ्रीज या इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है। चलिए, जानते हैं कि इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा कैसे एक्टिवेट करें?

एनपीएस अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करें

फ्रीज अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जिस बैंक में आपका एनपीएस अकाउंट ओपन होता है वहां से भी आप यह फॉर्म ले सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के बाद सब्सक्राइबर को PRAN कार्ड की कॉपी लगानी होगी।

इसके साथ ही अकाउंट होल्डर को सालाना बकाया राशि जमा करनी होगी और प्रति वर्ष के 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद अधिकारी द्वारा उसे वेरिफाई किया जाएगा।

एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होने के बाद प्रोसेस शुरू किया जाएगा और पीआरएएन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा।

एनपीएस वेबसाइट से कैसे करें अकाउंट एक्टिव

आप एनपीएस वेबसाइट (https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/nps.aspx) पर जाएं।

अब आप अपना पीआरएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

इसके बाद My account पर क्लिक करें।

अब आप Unfreeze account के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

इसके बाद आपको जरूरत की सभी जानकारी को भरना है और लेट फीस की पेमेंट करनी है।

एसबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट को लेकर आरबीआई से की बातचीत, कहा कैश रिजर्व रेश्यो को करना चाहिए कम

SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने बताया कि ग्रीन डिपॉजिट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बाचीत हो रही है। इस बातचीत का उद्देश्य ग्रीन डिपॉजिट में लोअर कैश रिजर्व को कम रखना है। बैंक नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को लेकर आरबीआई से बातचीत कर रहा है। एसबीआई ने पिछले महीने 1111 1777 और 2222 दिनों की टेन्योर वाली ग्रीन डिपॉजिट एफडी स्कीम शुरू की थी।

दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष दिनेश खारा ने बताया कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ग्रीन डिपॉजिट (Green Deposit) को लेकर बातचीत की है। इस बातचीत का उद्देश्य ग्रीन डिपॉजिट में लोअर कैश रिजर्व को कम रखना है।

दरअसल, एसबीआई ने पिछले महीने एक ग्रीन डिपॉजिट एफडी स्कीम (Green Deposit FD Scheme) की घोषणा की थी। यह पहली ग्रीन डिपॉजिट स्कीम है। इसका इस्तेमाल लॉन्ग-टर्म रिटेल के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग केवल हरित संक्रमण परियोजनाओं या जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा।

बैंक ने कहा कि ऐसी डिपॉजिट की कीमत सामान्य जमा दरों से 10 आधार अंक कम होगी। हालांकि, बैंक नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को लेकर आरबीआई से बातचीत कर रहा है। सीआरआर वह न्यूनतम राशि है जिसे किसी बैंक को अपनी कुल जमा राशि के मुकाबले केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में सीआरआर (Cash Reserve Ratio) 4.5 प्रतिशत पर आंका गया है, जिसका अर्थ है कि बैंक द्वारा जमा किए गए प्रत्येक एक रुपये में से 4.5 पैसे रिज़र्व बैंक के पास सॉल्वेंसी उपाय के रूप में रखे जाने चाहिए। बैंक आरबीआई के पास आरक्षित राशि पर कोई ब्याज नहीं कमाते हैं।

दिनेश खारा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही

हम ग्रीन डिपॉजिट के लिए सीआरआर में कटौती के लिए आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर यह एक नीति के रूप में है, तो इसे नियामक नीति तंत्र में शामिल किया जा सकता है। इसकी शुरुआत नियामक की ओर से भी हो चुकी है, लेकिन शायद इसमें समय लगेगा।

चेयरमैन ने यह भी कहा कि बैंक यह देखने के लिए रेटिंग संस्थाओं के साथ जुड़ रहा है कि क्या ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए एक लेखांकन मानक निर्धारित किया जा सकता है। एसबीआई ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन रेटिंग के आधार पर कर्जदारों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है।

बता दें कि दिनेश खारा से पहले प्रदीप चौधरी ने सीआरआर के तहत जमा पर आरबीआई से ब्याज भुगतान की मांग करने के बाद नियामक के साथ लंबी लड़ाई लड़ी थी।

एसबीआई ग्रीन डिपॉजिट स्कीम

एसबीआई ने पिछले महीने 1,111, 1,777 और 2,222 दिनों की टेन्योर वाली ग्रीन डिपॉजिट एफडी स्कीम शुरू की थी। इसमें बैंक में नियमित सावधि जमा की समान अवधि पर प्रचलित दरों से लगभग 10 आधार अंक कम ब्याज दरें थीं।

आरबीआई ने सावधि जमा स्वीकार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जो जून 2023 से लागू है। इस रूपरेखा के अनुसार, वित्तीय संस्थानों को हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का निर्णय लेने से पहले हरित जमा जुटाना होगा।

दस वर्षों में एमएसपी पर 18 गुना हुई दाल की सरकारी खरीद, दलहन का उत्पादन भी 60 प्रतिशत बढ़ा

एक दशक में दालों के उत्पादन में 60 प्रतिशत एवं एमएसपी पर इसकी खरीदारी में 18 गुना वृद्धि हुई है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम है कि एक दशक में हम चना एवं कुछ अन्य दलहन में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अरहर एवं उड़द में थोड़ी कमी रह गई है जिसे 2027 तक पूरा कर लेना है।

नई दिल्ली। भारत खाद्यान्न, दाल, सब्जियों एवं फलों का बड़ा उत्पादक बनता जा रहा है। दशक भर में दालों के उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 2014 में 171 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 270 लाख टन हो गया है।

चार दिवसीय पल्सेस कन्वेंशन की शुरुआत

दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में गुरुवार को नेफेड एवं ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (जीपीसी) द्वारा चार दिवसीय पल्सेस कन्वेंशन की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा एवं उपभोक्ता मामले तथा खाद्य-सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने की। कहा- भारत तेजी से दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

दालों के उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि

एक दशक में दालों के उत्पादन में 60 प्रतिशत एवं एमएसपी पर इसकी खरीदारी में 18 गुना वृद्धि हुई है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम है कि एक दशक में हम चना एवं कुछ अन्य दलहन में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अरहर एवं उड़द में थोड़ी कमी रह गई है, जिसे 2027 तक पूरा कर लेना है। नई किस्मों की बीज आपूर्ति व रकबा बढ़ाया जा रहा है। रबी सीजन में मसूर का रकबा एक लाख हेक्टेयर बढ़ा है।

देश में कृषि उत्पादन 3320 लाख टन का लक्ष्य है, जिसमें अकेले 292.5 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य है। गोयल ने बताया कि 2014 में देश में 171 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2024 में 60 प्रतिशत बढ़कर 270 लाख टन हो गया है।

खाद्य उत्पादों के उत्पादन और गुणवत्ता में विस्तार

विभिन्न खाद्य उत्पादों के उत्पादन और गुणवत्ता में विस्तार हुआ है, जिससे भारत 50 अरब डालर से अधिक के कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात करने लगा है। किसानों को सहारा एवं उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत दाल लांच की गई। चार महीने में ही बाजार के करीब 25 प्रतिशत हिस्से पर भारत दाल का कब्जा हो गया है।

पीएम मोदी के चढते ग्राफ को किसान आंदोलन लाएगा नीचे-डल्लेवाल- और खालिस्तानी- पन्नू

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली। एमएसपी को लेकर पंजाब के किसानों ने जमकर हरियाणा,दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सील किए गए बार्डर को फांदने की कोशिश की गई। किसान अपने-अपने ट्रैक्टरों में 6 महीनों का राशन लादे पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी पुलिस बंदोबस्त के तहत कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर खेतों में खेती तो सरकार ने सडकों पर लोहे की कीलों को गाढने की खेती शुरू कर दी है।सडकों ,बार्डरों पर रूकावटे खडी होने के बावजूद किसान पूरे आर-पार के मूढ में है।लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ दिल्ली और चंडीगढ में किसानों की बैठक अब तक बेनतीजा रही है।आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच पत्थर बाजी झड़पें जारी है। अब किसानों ने रेल की पटरियों पर भी कब्जा जमा लिया है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और-खालिस्तानी स्वभूं नेता पतवंत सिंह पन्नू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।वीडियो मे जगजीत सिंह डल्लेवाल पीएम मोदी की बढती लोकप्रियता और राम मंदिर से बढते ग्राफ का जिक्र कर रहे है। वीडियो में डल्लेवाल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि राम मंदिर की वजह से पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है।ऐसे में मोदी का ग्राफ कैसे नीचे आ सकता है? उन्होने कहा कि मैने बहुत बार लोगों से कहा है कि टाइम बहुत कम है और मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा है। उसको डाऊन करना बेहद जरूरी है। वहीं खालिस्तान स्वयंबू नेता पतवंत सिंह पन्नू का वीडियों भी खासा आपत्तिजनक है।जिसमें वह किसानो को भडकाने का काम कर रहा है। पतवंत सिंह पन्नू को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पंजाब दे किसानों दिल्ली से आजतक कुछ नहीं मिला है। बीती 13 फरवरी को दिल्ली पर कब्जा जमा लो। मोदी के घर पर खालिस्तान का झंडा लगा दो।जरा याद करो खालिस्तान के लिए शहीद हो गए संदीप सिंह सिद्दू, बलविंदर सिंह जटाने,चरणजीत सिंह चन्ने को और उठा लो हाथों में शमशीरें और टांग दो दिल्ली में झंडा खालिस्तान का। दिल्ली से चल रही हिंदू हुकुमत को उखाडना है, और दिल्ली को फतेह करना है। पंजाब की नस्लों और फसलों को आजाद कराना होगा। वहीं सडकों और बार्डरों पर किसानों के कब्जे से परशान आम आदमी ने आंदोलन के नाम पर सियासी रोटी सेंकने वाले कथित नेताओ का विरोध जताया है।

6 महीने के लिए हडताल पर पाबंदी,किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार का बडा फैसला

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए हडताल पर पाबंदी का फरमान जारी कर दिया है। उल्लंघन पर बिना वारंट के गिरफ्तारी के आदेश। इस बावत उत्तर प्रदेश सरकार का बडा फैसला माना जा रहा है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एम्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी,हडताल या प्रदान करते पाया जाता है तो हडताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए हडताल पर पाबंदी लगा दी है।यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागो,निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि 2023 में भी योगी सरकार ने 6 महीने के लिए इसी तरह की पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त बिजली विभाग के कर्मचारी हडताल पर चले गए थे।

अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थाक डॉ ह्रदयेश कुमार ने आम जन को डायबिटीज और शरीर में क्रिया से होने वाले बदलाव के लिए किया जागरूक

तिरखा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया स्वस्थ जीवन पर चर्चा

परिवहन विशेष न्यूज

फ़रीदाबाद। हरियाणा से अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ के लिए आम जन को अपनी अलग अलग तरीकों से जागरूक करने से लेकर उपचार के लिए सावधानियां बरतनी होगी आदि तरह तरह से अपनी छवि को समाज सेवा में समर्पित कर रहे हैं डॉ ह्रदयेश कुमार सिंह को अब तक 1200 से अधिक अवार्ड मिले हैं जिसमे विश्व रत्न सम्मान अवार्ड, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार और PRESTIGIO US BOOK OF WORLD RECORD तथा INTERNATIONAL STAR AWARD

अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड मे नवाजा गया है

डॉ ह्रदयेश कुमार ने बताया कि डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन पैदा करने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है। परिणामस्वरूप, शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है।

डायबिटीज वयस्कों में अधिक आम है, लेकिन यह बच्चों और किशोरों में भी विकसित हो सकता है। यह तब होता है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या ब्लड शुगर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है।

डायबिटीज अक्सर खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और अधिक वजन जैसे जीवनशैली कारकों से जुड़ा होता है।

स्थिति के शीघ्र निदान और प्रभावी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।बच्चों में डायबिटीज के शुरुआती संकेत*1. बार-बार पेशाब आना *अत्यधिक प्यास और बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का संकेत हो सकता है। बिस्तर गीला करने, बार-बार बाथरूम जाने या असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में पेशाब आने के लक्षणों पर गौर करें।

थकान बढ़ना *अज्ञात डायबिटीज से पीड़ित बच्चे पर्याप्त आराम करने के बाद भी थकान और सुस्ती महसूस कर सकते हैं।

घावों का धीरे-धीरे ठीक होना *घाव, कट या चोट को ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लगना डायबिटीज का संकेत हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर शरीर की ठीक होने की क्षमता को प्रभावित करती है।

मूड बदलना *चिड़चिड़ापन, मनोदशा में बदलाव, या अप्रत्याशित व्यवहार परिवर्तन चेतावनी के संकेत हो सकते हैं, खासकर अगर इसके साथ अत्यधिक प्यास या पेशाब जैसे अन्य लक्षण भी हों।

स्तब्ध हो जाना या झुनझुनी होनाडायबिटीज के कारण आमतौर पर हाथ, पैर या टांगों में सुन्नता या झुनझुनी जैसी असामान्य संवेदनाएं हो सकती हैं। इन लक्षणों के बारे में किसी भी शिकायत पर ध्यान दें।यदि आप इनमें से कोई भी शुरुआती संकेत देखते हैं, तो सटीक निदान पाने के लिए डॉ विशेषज्ञ से परामर्श करना अति आवश्यक है।

भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 - 18 फरवरी को दिल्ली में, भीलवाड़ा से जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों सहित 24 सदस्यीय दल लेगा हिस्सा

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 17 व 18 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। जिसमें भीलवाड़ा जिले से जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित जनप्रतिनिधियो एवं पदाधिकारियों का 24 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होता है इससे पूर्व यह अधिवेशन 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व आयोजित हुआ था। इसी क्रम में आयोजित हो रहे इस अधिवेशन का शुभारंभ 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम मे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उद्घाटन भाषण से होगा एवं 18 फरवरी को दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।

अधिवेशन में भीलवाड़ा से सांसद, पूर्व सांसद, जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, 6 विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा विस्तारक, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, निकाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियो का 24 सदस्यीय दल सम्मिलित होगा। अधिवेशन के लिए पंजीकरण 17 फरवरी को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा जिसमे सभी को डिजिटल माध्यम से शुल्क जमा कराना होगा। भीलवाड़ा से जाने वाले जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के आवास की व्यवस्था किसान भवन, पूसा कैम्पस में रहेगी।

हरियाणा सरकार द्वारा आपके लिए अभूतपूर्व छूट। शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि कर स्व-प्रमाणित करें एवं 29 फ़रवरी, 2024 तक प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट, मार्च 2023 तक के बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट और वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत छूट पाएं। भुगतान करने के लिए https://property.ulbharyana.gov.in/ पर जाएं। सादर डीयूएलबी हरियाणा।

शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज ने धूमधाम से मनाई सूर्यसप्तमी

बेंड बाजो के साथ निकली सूर्यदेव की शोभा यात्रा।

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर में शुक्रवार को जिला शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज संस्था की ओर से सूर्यसप्तमी का पर्व बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपरिषद के पूर्व उपसभापति दिनेश शर्मा ने की। वही मंचासीन अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समाज के प्रबुद्ध जनों ने आए हुए अतिथियों को माला व केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया।

कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगो ने शुक्रवार को सुबह 7.30 बजे भगवान भास्कर की पूजाअर्चना करते हुए सामुहिक सूर्यभगवान को अर्ध देते हुए सुंदरकांड का पाठ किया। बैंडबाजों की धून के साथ शोभायात्रा निकाली गई शोभायात्रा में समाज के पुरुषों ने सफेद कुर्ते पजामे व महिलाओं ने चूंदड़ की साड़ी पहने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते कूदते शोभायात्रा निकाली गई। वही समाज के भवन में पुरुष महिलाओं व बालक बालिकाओं ने कई विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को अथितियो ने पुरुष्कृत कर समाननित किया।

इस मौके पर छः न्यात ब्राह्मण के तुलसी राम शर्मा, परशुराम सेवा समिति से राजेंद्र सारस्वत, विप्र फॉउंडेशन के दीपक सुल्तानिया, ब्राह्मण महासभा से नरेश शर्मा,शाकद्वीपीय समाज के अध्यक्ष शिव लाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा सहित समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।

आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से कहा- बढ़ते जोखिमों को लेकर रहें सतर्क

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बुधवार को बैंकों से इस सेक्टर में बढ़ते जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा, उसने कहा कि आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है, गवर्नर ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों और प्राइवेट सेक्टर के चुनिंदा बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की,

यह आरबीआई की बैंकों, एनबीएफसी और उसके दायरे में आने वाली अन्य इकाइयों के सीनियर मैनेजमेंट के साथ निरंतर बातचीत करने की मुहिम का हिस्सा है, आरबीआई ने बयान में कहा कि गवर्नर ने बैंकों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की,

किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं

बयान के अनुसार बैंकों के स्वस्थ बहीखातों के साथ घरेलू वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर गौर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंकों को बढ़ते जोखिमों को लेकर अपनी निगरानी बनाए रखनी चाहिए, दास ने व्यापार मॉडल व्यवहार्यता, पर्सनल लोन्स में अत्यधिक वृद्धि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में बैंक के कर्ज और नकदी जोखिम प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया,

इन चीजों को मजबूत करने की बात की

उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा तैयारियों, परिचालन मजबूती, डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित मामलों और आंतरिक रेटिंग ढांचे को मजबूत करने की भी बात कही, बैठक में बैंकों को आरबीआई की वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) संबंधित पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने और डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को और बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, बैठक में डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जे के साथ-साथ विनियमन तथा निगरानी कार्यों की देख-रेख कर रहे कार्यकारी निदेशक भी शामिल हुए।

बिजेड़ी-बीजेपी समझौते में ईडी ने रेड की : कांग्रेस

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: अभियोजन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह बिजेड़ी विधायक प्रफुल्ल सामल के घर पर छापा मारा। इस मामले पर कांग्रेस ने फिर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस चुनाव में बिजेड़ी-बीजेपी की साझेदारी का आरोप लगाया है। उधर, बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण निष्कासन हुआ है। कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष शरत पटनायक ने कहा, बिजेड़ी के भीतर विद्रोह शुरू हो गया है। इसलिए बागियों को काबू में रखने के लिए बिजेड़ी-बीजेपी ने इस ईडी को खड़ा किया है। पिछले दो चुनावों में उनकी पार्टी के नेताओं ने बगावत नहीं की। इस बार नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। उन्हें डर है कि जो लोग उनकी पार्टी में बगावत करेंगे, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई उन्हें डरा देगी। शरत ने कहा कि अगर किसी नेता के घर में ईडी का काम पूरा हो गया तो बाकी लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे। विपक्षी दल के मुख्य सचिव और भाजपा नेता मोहन चरण माझी ने कहा, ओडिशा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। ईडी को अपना काम समय पर करने को कहा गया। मोहन ने कहा, ईडी कभी भी भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाती।

सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से लोहे का पाइप उखड़कर कार और स्कूटी पर गिरा, एक शख्स घायल

दिल्ली के कथित तौर पर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एक लोहे का पाइप उखड़कर एक कार और स्कूटी पर गिर गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स घायल हुआ है। आगे की जांच जारी है।

औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों/संघों का संयुक्त मंच

21 सूत्रीय मांगों का चार्टर

1. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखें, भोजन, दवाओं, कृषि-इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी हटाएं, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में काफी कमी करें।

2. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों, खिलाड़ियों को दी जाने वाली रेलवे रियायतें, जो कोविड के बहाने वापस ले ली गई थीं, बहाल की जाएं।

3. खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना।

4. सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को रद्द करें।

5. सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें।

6. वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, पुनर्स्थापन अधिनियम (एलएआरआर अधिनियम) 2013 का कड़ाई से कार्यान्वयन; वन (संरक्षण) अधिनियम, 2023 और जैव-विविधता अधिनियम और नियमों में संशोधन वापस लें जो केंद्र सरकार को निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते हैं। जोतने वाले को भूमि सुनिश्चित करें।

7. राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन रु. 26000/- प्रति माह।

8. भारतीय श्रम सम्मेलन नियमित रूप से बुलाना।

9. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करें और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को ख़त्म करें। खनिजों और धातुओं के खनन पर मौजूदा कानून में संशोधन करें और स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासियों और किसानों के उत्थान के लिए कोयला खदानों सहित खदानों से लाभ का 50% हिस्सा सुनिश्चित करें।

10. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 वापस लें। कोई प्री-पेड स्मार्ट मीटर नहीं।

11. काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाये। स्वीकृत पदों को भरें और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करें। मनरेगा का विस्तार और कार्यान्वयन (प्रति वर्ष 200 दिन और 600 रुपये प्रति माह मजदूरी)। शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बनायें।

12. किसानों को बीज, उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाएं, किसानों की उपज के लिए एमएसपी @ सी-2+50% की कानूनी गारंटी दें और खरीद की गारंटी दें। किसानों की आत्महत्याओं को हर कीमत पर रोकें।

13. कॉर्पोरेट समर्थक पीएम फसल बीमा योजना को वापस लें और जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, फसल संबंधी बीमारियों आदि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सभी फसलों के लिए एक व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना स्थापित करें।

14. सभी कृषक परिवारों को कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करें।

15. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू करें, जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को निलंबित कर दिया गया था: सभी शहीद किसानों के लिए सिंघू सीमा पर स्मारक, मुआवजा दें और उनके परिवारों का पुनर्वास करें, सभी लंबित मामलों को वापस लें, अजय मिश्रा टेनी, संघ पर मुकदमा चलाएं गृह राज्य मंत्री।

16. चार श्रम कोड वापस लें, कोई निश्चित अवधि का रोजगार नहीं और काम पर समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करें। श्रम का आकस्मिककरण बंद करें. असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियां, जैसे घर-आधारित श्रमिक, फेरीवाले, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू श्रमिक, निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, योजना श्रमिक, कृषि श्रमिक, दुकान/प्रतिष्ठानों में श्रमिक, लोडिंग/अनलोडिंग श्रमिक, गिग श्रमिक, नमक- पैन श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, ताड़ी निकालने वालों, रिक्शा चालकों, ऑटो/रिक्शा/टैक्सी चालकों, प्रवासी श्रमिकों, मछली पकड़ने वाले समुदाय आदि को पंजीकृत किया जाए और पेंशन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी दी जाए।

17. निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ईएसआई कवरेज दें, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं, मातृत्व लाभ, जीवन और विकलांगता बीमा का कवरेज भी दें।

18. घरेलू कामगारों और गृह-आधारित कामगारों पर आईएलओ कन्वेंशन की पुष्टि करें और उचित कानून बनाएं। प्रवासी श्रमिकों पर व्यापक नीति बनाएं, उनके सामाजिक सुरक्षा कवर की पोर्टेबिलिटी प्रदान करते हुए मौजूदा अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1979 को मजबूत करें।

19. एनपीएस ख़त्म करें, ओपीएस बहाल करें और सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। न्यूनतम पेंशन रु.10000 प्रति माह सुनिश्चित करें।

20. अत्यधिक अमीरों पर कर लगाएं; कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएँ; संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर पुनः लागू करें।

21. हिट एंड रन प्रावधानों सहित भारतीय न्याय संहिता के कठोर प्रावधानों को वापस लें।

संयुक्त किसान, मजदूर कर्मचारी एकता,

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023